

56/4



सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 5, 1985/आश्विन 13, 1907  
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 5, 1985/ASVINA 13, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं  
(Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the  
Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1985

आ. 4638—भारत सरकार के गृह मंत्रालय  
अधिसूचना संख्या का. आ. 692(अ), तारीख 25  
सितम्बर, 1985 के अधीन जालंधर न्यायिक जोन के संबंध  
में विशेष न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय  
सरकार यह निर्देश देती है कि श्री विनोद गुप्ता, जिला  
अदरनी, लुधियाना, जालंधर न्यायिक जोन में स्थापित विशेष  
न्यायालय के लोक अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985  
को त्याग देगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सेल]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th September, 1985

S.O. 4668.—Consequent on the abolition of the Special  
Court in relation to the judicial zone of Jalandhar under the  
notification of the Government of India in the Ministry of  
Home Affairs No. S.O. 692 (E) dated the 25th September,  
1985, the Central Government hereby direct that Shri Vinod  
Gupta, District Attorney, Ludhiana, will demit office of the  
Public Prosecutor of the Special Court established in relation  
to the judicial zone of Jalandhar, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

826 GI/85—1

(5297)

का. आ. 4669.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की  
अधिसूचना संख्या का. आ. 693(अ), तारीख 25 सितम्बर,  
1985 के अधीन पटियाला न्यायिक जोन के संबंध में विशेष  
न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार यह  
निर्देश देती है कि श्री सुरिंदर सिंह, जिला अदरनी, पटियाला,  
पटियाला न्यायिक जोन में स्थापित विशेष न्यायालय के लोक  
अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985 को त्याग देगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सेल]

S.O. 4669.—Consequent on the abolition of the Special  
Court in relation to the judicial zone of Patiala under the  
notification of the Government of India in the Ministry of  
Home Affairs No. S.O. 693(E) dated the 25th September,  
1985, the Central Government hereby direct that Shri Surinder  
Singh, District Attorney, Patiala, will demit office of the Pub-  
lic Prosecutor of the Special Court established in relation to  
the judicial zone of Patiala, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

का.आ. 4670.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 694(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 के अधीन फिरोज़पुर न्यायिक ज़ोन के संबंध में विशेष न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि श्री आर. के. आनन्द, जिला अटर्नी, फिरोज़पुर, फिरोज़पुर न्यायिक ज़ोन में स्थापित विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985 को त्याग देंगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सैल]

S.O. 4670.—Consequent on the abolition of the Special Court in relation to the judicial zone of Ferozepur under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 694(E) dated the 25th September, 1985, the Central Government hereby direct that Shri R. K. Anand, District Attorney, Ferozepur, will demit office of the Public Prosecutor of the Special Court established in relation to the judicial zone of Ferozepur, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

का.आ. 4671.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 695(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 के अधीन चण्डीगढ़ न्यायिक ज़ोन के संबंध में विशेष न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि श्री डी. एम. चिमनी, जिला अटर्नी, होशियारपुर, चण्डीगढ़ न्यायिक ज़ोन में स्थापित विशेष न्यायालय के लोक अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985 को त्याग देंगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सैल]

S.O. 4671.—Consequent on the abolition of the Special Court in relation to the judicial zone of Chandigarh under the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 695(E) dated the 25th September, 1985, the Central Government hereby direct that Shri D. S. Chimni, District Attorney, Hoshiarpur, will demit office of the Public Prosecutor of the Special Court established in relation to the judicial zone of Chandigarh, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85 Legal Cell]

का.आ. 4672.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 692(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 के अधीन जालंधर न्यायिक ज़ोन के संबंध में विशेष न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि 1. श्री कश्मीर सिंह, 2. श्री कुलदीप सिंह, 3. श्री बलदेव सिंह, 4. श्री यशपाल शर्मा, 5. श्री विक्रम लुम्बा, जालंधर न्यायिक ज़ोन में स्थापित विशेष न्यायालय के अपर लोक अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985 को त्याग देंगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सैल]

S.O. 4672.—Consequent on the abolition of the Special Court in relation to the judicial zone of Jalandhar under the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 692(F) dated the 25th September, 1985, the Central Government hereby direct that 1. Shri Kashmira Singh, 2. Shri Kuldip Singh, 3. Shri Baldev Singh, 4. Shri Yashpal Sharma, 5. Shri Vikram Loomba, will demit

office of the Additional Public Prosecutor of the Special Court established in relation to the judicial zone of Jalandhar, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85 Legal Cell]

का.आ. 4673.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 693(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 के अधीन पटियाला न्यायिक ज़ोन के संबंध में विशेष न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि 1. श्री मंगल सेन चड्ढा, 2. श्री हरभगत सिंह, 3. श्री पी. डी. शर्मा, 4. श्री कौर चन्द, पटियाला न्यायिक ज़ोन में स्थापित विशेष न्यायालय के अपर लोक अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985 को त्याग देंगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सैल]

S.O. 4673.—Consequent on the abolition of the Special Court in relation to the judicial zone of Patiala under the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 693(F) dated the 25th September, 1985, the Central Government hereby direct that Shri Mangal Sen Chadha, 2. Shri Harbhagat Singh, 3. Shri P. D. Sharma, 4. Shri Kaur Chand will demit office of the Additional Public Prosecutor of the Special Court established in relation to the judicial zone of Patiala, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

का.आ. 4674.—भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 694(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 के अधीन फिरोज़पुर न्यायिक ज़ोन के संबंध में विशेष न्यायालय के उत्सादन के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सरकार यह निदेश देती है कि 1. श्री बलजीत सिंह, 2. श्री हरबंस सिंह, 3. श्री जे. सी. कक्कर, फिरोज़पुर न्यायिक ज़ोन में स्थापित विशेष न्यायालय के अपर लोक अभियोजक का पद 28 सितम्बर, 1985 को त्याग देंगे।

[सं. 1/8/85-लीगल सैल]

के. सी. श्रीवास्तव, अवर सचिव

S.O. 4674.—Consequent on the abolition of the Special Court in relation to the judicial zone of Ferozepur under the Notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. S.O. 694(F) dated the 25th September, 1985, the Central Government hereby direct that 1. Shri Bal Singh, 2. Shri Harbans Singh, 3. Shri J. C. Kakkar will demit office of the Additional Public Prosecutor of the Special Court established in relation to the judicial zone of Ferozepur, on 28th September, 1985.

[No. 1/8/85-Legal Cell]

K. C. SRIVASTAVA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1985

आयकर

का.आ. 4675.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-ग की उपधारा (2)(ख) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "श्री राजा राजेश्वर मन्दिर, तालिपारम्बा" को सम्पूर्ण केरल राज्य में प्रख्यात सार्वजनिक पूजा स्थल के रूप में अधिसूचित करती है।

[संख्या 6377/फा०सं० 176/20/84-आ०क० (नि०-1)]

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)

New Delhi, the 22nd August, 1985  
(INCOME-TAX)

S.O. 4675.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2)(b) of Section 80-G of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Sri Raja Rajeswara Temple, Taliparamba" as a place of public worship renowned throughout the State of Kerala.

[No. 6377/F. No. 176/20/84-IT (AI)]

का०आ० 4676.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23 ग) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "मिर्जा आगियारी एण्ड पारसी अंजुमन, जामनगर" को कर निर्धारण-वर्ष 1982-83 से 1985-86 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं० 6376/फा०सं० 197/87/83-आ०क० (नि०-1)]

S.O. 4676.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Mirza Agiari and Parsi Anjuman, Jamnagar" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1982-83 to 1985-86.

[No. 6376/F. No. 197/87/83-IT (AI)]

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 1985

का०आ० 4677.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23 ग) के उपखण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "हिन्दू सत्कार समिति, कलकत्ता" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित

[सं० 6394/फा०सं० 197-ए/45/82-आ०क० (नि०-1)]

New Delhi, the 29th August, 1985

S.O. 4677.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Hindu Satkar Samity, Calcutta" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6394/F. No. 197-A/45/82-IT (AI)]

का०आ० 4678.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खण्ड (23 ग) के उपखण्ड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा, उक्त धारा के प्रयोजनार्थ, "श्री रानी सतीजी

मन्दिर, जूनुहुन" को कर-निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 के अन्तर्गत आने वाली अवधि के लिये अधिसूचित करती है।

[सं० 6393/फा०सं० 197-ए/60/82-आ०क० (नि०-1)]  
आर० के० तिवारी, अवर सचिव

S.O. 4678.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (v) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies "Shree Rani Satiji Mandir, Jhunjunu" for the purpose of the said section for the period covered by the assessment years 1985-86 to 1987-88.

[No. 6393/F. No. 197-A/60/82-IT (AI)]  
R. K. TEWARI, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1985

आयकर

का०आ० 4679.—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खण्ड (44) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में और भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 25-2-1983 का अधिसूचना सं० 5106 (फा०सं० 398/8/83-आ०क० (ब०)) का अधिलेखन करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री ए० स्वामी नायडू को, जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारों को शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

2 यह अधिसूचना 31-8-1985 से लागू होगी।

[सं० 6398/फा०सं० 398/22/85-आ०क० (ब०)]  
बी० ई० एलेक्जेंडर, अवर सचिव

New Delhi, the 30th August, 1985

INCOME-TAX

S.O. 4679.—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (44) of Section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Notification of the Government of India in the Department of Revenue No. 5106 (F. No. 398/8/83-IT(B)) dated 25-2-1983 the Central Government hereby authorises Shri A. Swamy, Naidu being a Gazetted Officer of Central Government to exercise the powers of a Tax Recovery Officer under the said Act.

2. This Notification shall come into force with effect from 31-8-1985.

[No. 6398/F. No. 398/22/85-IT (B)]  
B. F. ALEXANDER, Under Secy.

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 1985

स्टाम्प

का०आ० 4680.—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा मैसूर दि हिन्दुस्तान स्पॉन्सिंग एण्ड वॉशिंग मिल्स लिमिटेड बम्बई को केवल निगम के तौर पर

द्वारा ज्ञान से पचास रुपये के उस समेकित स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की अनुमति देती है, जो उक्त कर्पन द्वारा जारी किये जाने वाले एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये के अंकित मूल्य के 15 प्रतिशत आरक्षित परिणोध्य ऋण पत्रों (क्रम संख्या 1 से 1,25,000) पर प्रभावी है।

[सं० 33/85-स्टाम्प-फा० सं० 33/42/85-वि० क०]

बी०आर० मेहता, अवर सचिव

(Department of Finance)

ORDER

New Delhi, the 16th September, 1985

STAMPS

S.O. 4680.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), the Central Government hereby permits M/s. The Hindustan Spinning and Weaving Mills Ltd. Bombay to pay consolidated stamp duty of Ninety-three thousand seven hundred and fifty rupees only, chargeable on account of the stamp duty on the 15 per cent secured Redeemable Debentures bearing serial numbers 1 to 1,25,000 of the face value of one crore and twenty five lakhs rupees to be issued by the said Company.

[No. 34/85-Stamps/F. No. 33/42/85-ST]

B. R. MEHMA, Under Secy.

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बीमा प्रभाग)

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1985

सा० का० 4681—जावन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31वा) का धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय जावन बीमा निगम के वर्तमान प्रभारी और प्रबन्ध निदेशक श्री ए०एस० गुप्ता, को कार्य ग्रहण करने का तारख से और उनको सेवा निवृत्ति का तारख अर्थात् 30 नवम्बर, 1986 तक निगम का अध्यक्ष नियुक्त करता है।

[फाइल सं० 108/2/85-इण्डो-1]

आर०एन० भट्टाचार्य, निदेशक (बीमा)

(Department of Economic Affairs)

(Insurance Division)

New Delhi, the 9th September, 1985

S.O. 4681.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri A. S. Gupta, Current-in-Charge & Managing Director as Chairman of the Life Insurance Corporation of India with effect from the date of assumption of charge and up to 30th November, 1986, the date of his superannuation.

[F. No. 108/2/85-Ins. IV]

R. N. BHATTACHARYA, Director (Insurance)

पेट्रोलियम मंत्रालय

नई दिल्ली 25 सितम्बर, 1985

सा.प्र. 4682—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) क भाग 3 की उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का सा.सं 3207 तारीख 4-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों का बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

यस अधिन उक्त अधिनियम क धारा 6 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियां में उपयोग के अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाभा है।

और आगे उक्त अधिनियम क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में विहित होते के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि में सुम. बाधाओं से मुक्त रूप में बोधना के प्रकाशन का उस तारीख को विहित होगा।

अनुसूची

हजीरा से बरेली में जगदौशपुर तक पाइप लाइन बिछाने के लिए

राज्य : गुजरात	जिला : सुरत	तालुका	मांगरोल	
गांव	ब्लाक नं.	हेक्टेयर	आर	सेन्टीयर
कोमवा	423	0	15	00
	424	0	18	00
	425	0	25	00
	126	0	27	00
	318/1	0	35	40
	329	0	23	40
	328	0	10	50
	331/2	0	28	50
	327	0	03	70
	329/पी	0	20	00
	221	0	14	40
	222	0	01	10
	226	0	20	36
	224	0	28	50
	223	0	22	80
	208	0	19	75
	228/3	0	14	88
	207	0	25	50
	206	0	21	00

[सं. O-14016/376/85-जीपी]

MINISTRY OF PETROLEUM

New Delhi, the 25th September, 1985

S.O. 4682.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3207 dated 4-7-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification,

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of powers conferred by sub-section (4) of that section the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

Pipeline from Hajira to Bareilly to Jagdishpur

State : Gujarat District : Surat Taluka : Mangrol

Village	Block No.	Hectare	Acre	Centiare
Kosamba	423	0	15	00
	424	0	18	00
	425	0	25	00
	426	0	27	00
	318/1	0	35	40
	329	0	23	40
	328	0	10	50
	331/2	0	28	50
	327	0	03	70
	229/P	0	20	00
	221	0	14	40
	222	0	01	10
	226	0	20	36
	224	0	28	50
	223	0	22	80
	208	0	19	75
	228/3	0	14	88
	207	0	25	50
	206	0	21	00

[No. O-14016/376/85-GP]

का. आ. 4683.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं० आ० सं० 3895 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें दे दी हैं।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्टें पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में बाधना के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

### अनुसूची

हाजिरा बरेली में जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला :	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	नवादा	448	1-1-15
			वीरान	447	0-12-15
				407	0-0-15
				392	0-3-0
				391	0-12-15
				388	0-5-5
				387	0-5-5
				385	0-4-5
				383	0-0-15

[सं. O-14016/443/85-जीपी]

S.O. 4683.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3895 dated 17-8-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Nawada	448	1-1-15
			Viran	447	0-12-15
				407	0-0-15
				392	0-3-0
				391	0-12-15
				388	0-5-5
				387	0-5-5
				385	0-4-5
				383	0-0-15

[No. O-14016/443/85-GP]

का. आ. 4684-—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्थात् भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3903 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना में गंलवन अनुसूची में बिलिखित भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आगव घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अर्थात् सरकार को रिपोर्टें दे दी हैं।

और आगे यतः केन्द्रिय सरकार ने उक्त रिपोर्टें पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में गंलवन अनुसूची में बिलिखित भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार द्वारा घोषित किया है कि इस अधिसूचना में गंलवन अनुसूची में बिलिखित उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय

गैस प्राधिकरण लि. में गैस बाधाओं से मुक्त कर में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	शेखपुरा उर्फ बिहारीपुर	573	0-3-15

[सं. O-14016/451/85-जी पी]

S.O. 4684.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3903 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Shekhu- pur u/f Biharipur	573	0 3-15

[No. O 14016/451/85-GP]

का०अ० 34685:—यह पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०अ० सं० 3891 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना अधिकार धारित कर दिया था।

और यह: मध्यम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है।

और आगे यह केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इन अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे इस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार से निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंबला	आंबला	नगरिया	406	1-1-10
			देहजयनी	403	0-2-0
				402	0-2-0
				391	0-5-0
				389	0-0-10
				392	0-18-0
				393	0-6-0
				379	0-0-10
				369	0-2-10
				371	0-5-0
		372	0-5-0		

1	2	3	4	5	6
				378	0-0-15
				376	1-15-0
				375	0-0-0
				342	0-0-10
				330	0-14-10
				331	0-8-0
				332	0-2-0
				333	0-14-0
				72	0-2-10
				71	1-1-10
				70	1-9-0
				57	0-7-0
				56	0-8-10
				55	0-6-0
				33	0-3-3
				24	0-0-2
				25	0-0-10
				23	0-3-0
				22	0-10-0
				21	0-5-10
				20	0-8-0
				34	0-2-0
				17	1-13-0
				18	0-0-10
				15	0-0-10
				16	0-0-10
				1	0-5-0

[सं. O-14016/438/85-जीपी]

S.O. 4685.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3891 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana Village	Plot No.	Area acquired
1	2	3	4	5
Bareilly	Awala	Nagariya	406	1 1 10
		Dchjayti	403	0 2 0
			402	0 2 0
			391	0-5 0
			389	0 0-10
			392	0-18 0
			393	0-6-0
			379	0-0-10
			369	0-12 10
			371	0-5-0
			372	0-5-0
			378	0-0-15
			376	1-15-0
			375	0-0-10
			342	0-0-10
			330	0-14-10
			331	0-8-0
			332	0-2-0
			333	0-14-0
			72	0-2-10
			71	1-1-10
			70	1-9 0
			57	0-7-0
			56	0-8-10
			55	0-6-0
			33	0-3-3
			24	0-0-2
			25	0 0-10
			23	0-3-0
			22	0-10-0
			21	0-5-10
			20	0-8-0
			34	0-2-0
			17	1-13-0
			18	0-0-10
			15	0-0-10
			16	0-0-10
			1	0-5-0

[No. O-14016/438/85-GP]

का. आ. 4686.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग का अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3901 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे का है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में धारणा के प्रकाश की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं. लिया गया रकबा (एकड़ में)

1	2	3	4	5	6
बरेली	आवला	आवला	पथरी	484	0-0-10
				490	0-3-15
				485	0-8-5
				489	0-16-0
				488	0-3-10
				487	0-4-15
				511	0-4-5
				417	0-13-15
				418	0-2-0
				420	0-2-0
				419	0-16-15
				407	0-5-0
				406	0-2-0
				352	0-3-15
				351	0-10-0
				354	0-0-10
				350	0-4-10
				340	0-4-10
				339	0-8-0
				337	0-0-5



1	2	3	4	5	6
				338	0-0-15
				336	0-6-10
				303	0-6-10
				302	0-6-10
				301	0-6-0
				298	0-0-5
				297	0-1-0
				294	0-2-10
				299	0-13-0
				271	0-0-10
				273	0-0-3
				272	0-0-2
				274	1-3-0
				279	0-17-0
				280	0-1-0
				283	0-0-10
				282	0-0-5
				259	0-5-10
				255	0-0-5
				257	0-0-15
				254	0-3-10
				184	0-4-10
				185	0-4-0
				186	0-18-0
				252	0-9-0
				187	0-8-10
				188	0-9-10
				189	0-7-0
				195	0-12-0
				196	0-1-0
				197	0-0-10
				193	0-2-10
				199	0-7-10
				201	0-5-0
				204	0-2-0
				198	0-0-10
				230	0-7-5
				231	0-11-0
				228	0-3-10
				203	0-0-5
				170	0-0-5
				177	0-0-10
				292	0-0-5
				256	0-0-5
				362	0-0-5
				200	0-3-10

S.O. 4686.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3901 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas, the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### H. B. J. Gas Pipeline Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Pathari	484	0-0-10
				490	0-3-15
				485	0-8-5
				489	0-16-0
				488	0-3-10
				487	0-4-15
				511	0-4-5
				417	0-13-15
				418	0-2-0
				420	0-2-0
				419	0-16-15
				407	0-5-0
				406	0-2-0
				352	0-3-15
				351	0-10-0
				354	0-0-10
				350	0-4-10
				340	0-4-10
				339	0-8-0
				337	0-0-5
				338	0-0-15
				336	0-6-10
				303	0-6-10
				302	0-6-10
				301	0-6-0
				298	0-0-5
				297	0-1-0
				294	0-2-10

स. O-14016/449/85-जीपी]

1	2	3	4	5	6
				299	0-13-0
				271	0-0-10
				273	0-0-3
				272	0-0-?
				274	1-3-0
				279	0-17-10
				280	0-1-0
				283	0-0-10
				282	0-0-5
				259	0-5-10
				255	0-0-5
				257	0-0-15
				254	0-3-10
				184	0-4-10
				185	0-4-0
				186	0-18-0
				252	0-9-0
				187	0-8-10
				188	0-9-10
				189	0-7-0
				195	0-12-0
				196	0-1-0
				197	0-0-10
				193	0-2-10
				199	0-7-10
				201	0-5-0
				204	0-2-0
				198	0-0-10
				230	0-7-5
				231	0-11-0
				228	0-3-10
				203	0-0-5
				170	0-0-5
				177	0-0-10
				292	0-0-5
				256	0-0-5
				362	0-0-5
				200	0-3-10

[No. O-14016/449/85-GP]

का० आ० 4687.-यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ०मं० 3894 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सश्रम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें दे दी हैं।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं में मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
बरेली	आवला	सन्हा	पखुरनी	217	0-1-10
				216	0-2-15
				9	0-12-0
				8	0-13-15
				6	1-2-15
				7	0-1-0
				5	0-11-5
				4	0-15-10
				3	0-1-0
				2	0-0-15
				1	0-15-5

[सं. O-14016/442/85-जीपी]

S.O. 4687.-Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3894 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

### SCHEDULE

#### H. B. J. Gas Pipe line Project

Distt	Tehsil	Pargana	Villago	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Pakharni	217	0-1-10
				216	0-2-15
				9	0-12-0
				8	0-13-15
				6	1-12-15
				7	0-1-0
				5	0-11-5
				4	0-15-10
				3	0-1-0
				2	0-0-15
				1	0-15-5

[No. O-14016/442/85-GP]

का० आ० 4688—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3902 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना ने संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप

लाइन बिछाने के प्रयाजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है, कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में बोवणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

### अनुसूची

#### हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा (एकड़ में)
1	2	3	4	5	6
बरेली	आबला	आबला	महातिया	125	0-5-10
			डांडो	480	0-1-10
				494	0-1-0
				481	0-1-0
				495	0-6-0
				493	0-14-0
				492	0-0-10
				496	0-14-0
				497	0-0-5
				375	0-0-5

[सं. O-14016/450/85-जी पी]

S.O. 4688.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3902 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## अनुसूची

## H. B. J. Gas Pipeline Project

## हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Mahaitiya	125	0-5-10
				480	0-1-10
			Dadri	494	0-1-0
				481	0-1-0
				495	0-6-0
				493	0-14-0
				492	0-0-10
				496	0-14-0
				497	0-0-5
				375	0-0-5

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुल्शनौर	अरुद्रपुर	सुल्तानगढ़	354	0-9-10
				364	0-1-0
				377	0-8-10
				378	0-7-0
				379	1-11-0
				386	1-0-0
				389	0-4-0
				390	0-15-10
				395/	0-5-10
				1069	
				391	0-4-10
				395	0-19-18
				394	0-13-10
				393	0-10-0
				396	0-0-15
				397	1-12-10
				401	0-2-0
				480	0-17-0
				481	0-11-0
				482	0-16-4
				483	0-7-10
				485	0-12-0
				486	0-1-0
				487	0-14-10
				488	0-3-0
				478	0-1-0
				477	1-2-0
				512	3-4-16
				514	0-6-0
				506	0-1-0
				903	0-17-0
				904	0-17-0
				910	1-1-0
				909	0-8-10
				907	0-10-15
				940	0-1-0
				892	0-9-0
				893	0-7-10
				894	0-0-10
				895	0-3-12

[No. O-14016/450/85-GP]

का०आ० 4689.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 3922, तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

1	2	3	4	5	6
				837	0-2-8
				852	0-0-10
				858	0-2-10
				857	1-2-10
				860	0-0-15
				863	0-11-8
				864	0-12-0
				865	0-2-10
				867	0-12-10
				790	1-0-0
				789	0-12-0
				788	0-13-0
				774	0-0-12
				773	0-6-0
				772	0-8-10
				768	0-12-0
				775	0-1-0
				776	1-0-0
				779	0-0-15
				778	0-19-16
				777	0-15-15
				591	0-3-0
				618	0-12-10
				619	0-4-18
				625	0-0-15
				626	0-4-18
				624	1-18-10
				622	1-9-0
				623	0-0-11
				352	0-0-5
				375	0-0-10
				513	0-1-0
				906	0-1-15
				853	0-16-0
				862	0-1-0
				776	0-0-15
				891	0-1-0
				766	0-0-10

[सं. O-14016/462/85-जी पी]

S.O. 4689.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3922 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## H. B. J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-	Asod-	Sultan-	354	0-9-10
	nour	pur	ganj	364	0-1-0
				377	0-8-10
				378	0-7-0
				379	1-11-0
				386	1-0-0
				389	0-4-0
				390	0-15-10
				395/1069	0-5-10
				391	0-4-10
				395	0-18-18
				394	0-13-10
				393	0-10-0
				396	0-0-15
				397	1-12-10
				401	0-2-0
				480	0-17-0
				481	0-11-0
				482	0-16-4
				483	0-7-10
				485	0-12-0
				486	0-1-0
				487	0-14-10
				488	0-3-0
				478	0-1-0
				477	1-2-0
				512	3-4-16
				514	0-6-0
				506	0-1-0
				903	0-17-0
				904	0-17-0
				910	1-1-0
				909	0-8-10
				907	0-10-15
				940	0-1-0
				892	0-9-0
				893	0-7-10

1	2	3	4	5	6
Badaun (Contd.)					
	894	0-0-10			
	895	0-3-12			
	837	0-2-8			
	852	0-0-10			
	858	0-2-10			
	857	1-2-10			
	860	0-0-15			
	863	0-11-8			
	864	0-12-0			
	865	0-2-10			
	867	0-12-10			
	790	1-0-0			
	789	0-12-0			
	788	0-13-0			
	774	0-0-12			
	773	0-6-0			
	772	0-8-10			
	768	0-12-0			
	775	0-1-0			
	776	1-0-0			
	779	0-0-15			
	778	0-19-16			
	777	0-15-15			
	591	0-3-0			
	618	0-12-10			
	619	0-4-18			
	625	0-0-15			
	626	0-4-18			
	624	1-18-10			
	622	1-9-0			
	623	0-0-11			
	352	0-0-5			
	375	0-0-10			
	513	0-1-0			
	906	0-1-15			
	853	0-16-0			
	862	0-1-0			
	776	0-0-15			
	891	0-1-0			
	766	0-0-10			

[No. O-14016/462/85-G.P.]

का. आ. 4690.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का.आ.सं. 1734 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिसौली	इस्लामनगर	नीगवा	407	0-1-15
				406	0-10-0
				401	0-4-10
				400	0-1-0
				415	0-11-5
				416	0-11-0
				413	0-6-0
				417	0-0-5
				425	0-6-0
				423	0-7-0
				422	0-10-5
				426	0-4-0
				424	0-0-15
				353	0-4-10
				351	0-7-10
				439	0-7-15
				440	0-1-0
				350	0-2-0
				349	0-10-0
				346	0-12-0
				345	0-3-5
				340	0-10-0

1	2	3	4	5	6
				338	0-4-0
				336	0-1-0
				69	0-4-0
				71	0-3-0
				72	0-4-0
				141	0-7-0
				142	0-9-0
				138	0-4-0
				120	0-1-5
				145	0-19-5
				146	0-18-0
				147	0-5-0
				169	0-7-0
				168	0-5-0
				164	0-2-0
				163	0-16-0
				162	0-5-10
				187	0-2-10
				188	0-6-0
				189	0-16-15
				190	0-5-0
				192	0-2-0
				193	0-1-15
				195	0-7-0
				196	0-0-5
				198	0-7-0
				200	0-3-0
				236	0-11-0
				237	0-2-0
				241	1-0-0
				242	0-10-0
				243	0-4-0
				244	0-0-10
				251	0-2-10
				252	0-4-0
				414	0-0-5
				159	0-1-0
				186	0-1-0
				194	0-1-0
				199	0-1-0
				161	0-3-0

lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### Hajira-Bareilly-Jagdishpur Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plct No	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam-Nagar	Nauga-van	407	0-1-15
				406	0-10-0
				401	0-4-10
				400	0-1-0
				415	0-11-5
				416	0-11-0
				413	0-6-0
				417	0-0-5
				425	0-6-0
				423	0-7-0
				422	0-10-5
				426	0-4-0
				424	0-0-15
				353	0-4-10
				351	0-7-10
				439	0-7-15
				440	0-1-0
				350	0-2-0
				349	0-10-0
				346	0-12-0
				345	0-3-5
				340	0-10-0
				338	0-4-0
				336	0-1-0
				69	0-4-0
				71	0-3-0
				72	0-4-0
				141	0-7-0
				142	0-9-0
				138	0-4-0
				120	0-1-5
				145	0-19-5

[सं. O-14016/279/85-जी पी]

S.O. 4690.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1734 dated 27-4-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the

1	2	3	4	5	6	
				146	0-18-0	एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ।
				147	0-5 0	
				169	0-7-0	
				168	0-5-0	
				164	0-2-0	और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।
				163	0-16-0	
				162	0-5-10	
				187	0-2-10	
				188	0-6-0	
				189	0-16-15	
				190	0-5-0	
				192	0-2 0	
				193	0-1-15	
				195	0-7-0	
				196	0-0-5	
				198	0-7-0	
				200	0-3-0	
				236	0-11-0	
				237	0-2-0	
				241	1-0-0	
				242	0-10-0	
				243	0-4-0	
				244	0-0-10	
				251	0-2-10	
				252	0-4-0	
				414	0-0-5	
				159	0-1-0	
				186	0-1-0	
				194	0-1-0	
				199	0-1-0	
				161	0-3-0	

## अनुसूची

## हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला बेहरा	लालच	213	1-2-15
				211	0-8-15
				212	0-1-5
				210	0-3-10
				209	0-15-0
				222	0-1-5
				208	0-3-15
				224	0-11-5
				223	0-14-10
				253	0-4-0
				249	0-19-10
				262	0-1-5
				243	0-1-0
				263	0-1-10
				264	0-12-5
				266	0-4-5
				267	0-0-2
				268	0-1-5
				270	0-9-0
				272	0-0-10
				271	0-4-0
				285	0-0-10
				284	0-1-0
				304	0-19-5
				303	0-7-5
				302	0-8-10
				305	0-1-0
				300	0-10-0
				299	0-4-5
				298	0-1-10

[No. O-14016/279/85-GP]

का. आ. 4691.—प्रतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3900 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार



1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				306	0-0-15					249	0-19-10
				311	0-2-05					262	0-1-5
				312	0-9-10					243	0-1-0
				314	0-8-10					263	0-1-10
				316	0-0-5					264	0-12-5
				317	0-9-10					266	0-4-5
				318	0-13-5					267	0-0-2
				323	0-4-0					268	0-1-5
				324	0-0-10					270	0-9-0
				325	0-0-10					272	0-0-10
				215	0-4-0					271	0-4-0

[सं. O-14016/448/85-जीपी]

S.O. 4691.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3900 dated 17-8-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government :

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Behala	213	1-2-15
			Lalach	211	0-8-15
				212	0-1-5
				210	0-3-10
				209	0-15-0
				222	0-1-5
				203	0-3-15
				224	0-11-5
				223	0-14-10
				253	0-4-0

[No. O-14016/448/85-GP]

क्र० आ० 4692.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिभार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना क्र० आ० सं० 3897 तारीख 9-1-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिभार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आग्रह घोषित कर दिया था ।

और, यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ।

और, आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिभार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ।

अब, आगे : उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेदन देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला तहसील परगना गांव गाटा सं लिया गया रकबा (एकड़ में)

1	2	3	4	5	6
बरेली	आंबल	आंबल	इस्लामाबाद	350	0-19-5
				351	0-2-0
				352	0-2-0
				353	0-0-15
				854	0-8-0
				355	0-2-5
				356	0-2-0
				357	0-0-10
				358	0-0-15
				366	0-17-5
				365	0-1-10
				361	0-3-10
				386	0-16-15
				399	1-15-0
				398	0-16-0
				404	0-0-15
				405	0-6-10
				403	1-4-0
				430	0-1-15
				419	0-1-0
				429	0-13-10
				428	0-12-10
				422	0-12-10
				423	0-4-5
				424	0-3-15
				436	2-2-0

1	2	3	4	5	6
				452	1-16-0
				450	0-13-0
				451	0-0-15
				805	0-11-0
				804	0-2-0
				802	0-1-10
				792	0-9-10
				783	0-2-10
				782	0-7-15
				773	0-1-0
				772	0-18-0
				758	0-3-15
				760	0-5-0
				761	0-5-0
				762	0-8-10
				763	0-1-10
				759	0-0-15
				745	0-3-10
				744	0-7-0
				742	0-0-15
				741	0-4-0

[सं. O-14016/445/85-जी पी]

S.O. 4692.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3897 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas, the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests from this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd, free from all encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Islama-	350	0-19-5
			bad	351	0-2-0
				352	0-2-0
				353	0-0-15
				354	0-8-0
				355	0-2-5
				356	0-2-0
				357	0-0-10
				358	0-0-15
				360	0-17-5
				365	0-1-10
				361	0-3-10
				386	0-16-15
				399	1-15-0
				398	0-16-0
				404	0-0-15
				405	0-0-10
				403	1-4-0
				430	0-1-15
				419	0-1-0
				429	0-13-10
				428	0-12-10
				422	0-12-10
				423	0-4-5
				424	0-3-15
				430	2-2-0
				452	1-16-0
				450	0-13-0
				451	0-0-15
				805	0-11-0
				804	0-2-0
				802	0-1-10
				792	0-9-10
				783	0-2-10
				782	0-7-15
				773	0-1-0
				772	0-18-0
				758	0-3-15
				760	0-5-0
				761	0-5-0
				762	0-8-10
				763	0-1-10
				759	0-0-15
				745	0-3-10
				744	0-7-0
				742	0-0-15
				741	0-4-0

कां०आ० 4693.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिसूचना कां०आ० नं० 3893 तारीख 17-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइन को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना अधिकार घोषित कर दिया था।

और, यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगी।

## अनुसूची

## हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाँवों से लिया गया रकबा (एकड़ में)	
1	2	3	4	5	6
बरेली	आवला	आवला	करतला	23	1-5-0
			उर्फ	24	0-7-0
			कसबा-	25	0-0-10
			ताल	26	0-3-0
				27	0-2-10
				28	0-2-0
				13	0-7-0
				14	0-13-0
				16	0-0-10
				160	0-3-0
				162	0-5-10
				173	0-2-0

1	2	3	4	5	6	SCHEDULE					
						H.B.J. Gas Pipe Line Project					
				174	0-7-0	Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
				175	0-0-5						
				180	0-2-0						
				181	0-2-0						
				179	1-10-0						
				182	0-2-0						
				184	0-2-10						
				185	0-5-0						
				186	0-3-0						
				187	0-3-0						
				190	0-5-10						
				191	0-11-0						
				192	0-0-10						
				193	0-2-0						
				194	0-1-10						
				195	0-4-0						
				197	0-3-10						
				198	0-5-0						
				199	0-14-0						
				262	0-12-0						
				263	0-1-0						
				264	0-0-5						
				270	0-5-0						
				271	0-7-10						
				272	0-0-10						
				273	0-8-0						
				276	0-1-0						
				277	0-15-0						
						Bareilly	Awala	Awala	Kartala	23	1-5-0
									urf	24	0-7-0
									Karua-	25	0-0-10
									tal	26	0-3-0
										27	0-2-10
										28	0-2-0
										13	0-7-0
										14	0-13-0
										16	0-0-10
										160	0-3-0
										162	0-5-10
										173	0-2-0
										174	0-7-0
										175	0-0-5
										180	0-2-0
										181	0-2-0
										179	1-10-0
										182	0-2-0
										184	0-2-10
										185	0-5-0
										186	0-3-0
										187	0-3-0
										190	0-5-10
										191	0-11-0
										192	0-0-10
										193	0-2-0
										194	0-1-10
										195	0-4-0
										197	0-3-10
										198	0-5-0
										199	0-14-0
										262	0-12-0
										263	0-1-0
										264	0-0-5
										270	0-5-0
										271	0-7-10
										272	0-0-10
										273	0-8-0
										276	0-1-0
										277	0-15-0

[सं. O-14016/440/85-जी पी]

S.O. 4693.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3893 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

[No. O-14016/440/85—GP]

का० प्र० 4694.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की द्वारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० प्र० सं० 1771 तारीख 27-4-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न प्रपञ्ची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

यव, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस शर्त पर निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	विशौली	इस्लामनगर	नूरपुर	34	0-1-15
			पिनानी	33	0-15-6
				32	1-0-0
				31	1-10-0
				29	0-1-0
				28	0-17-8
				20	0-0-15
				18	1-7-15
				16	0-9-0
				53	0-1-16
				55	1-2-15
				58	0-19-0
				59	0-2-0
				60	1-12-10
				61	1-7-12
				62	0-7-16
				36	0-1-0
				35	0-1-0
				37	1-8-0
				30	0-1-0

S.O. 4694—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 1771 dated 27-4-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

Hajira Bareilly Jagdishpur Pipeline Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Noorpur	34	0-1-15
			Pinauni	33	0-15-6
				32	1-0-0
				31	1-10-0
				29	0-1-0
				28	0-17-8
				20	0-0-15
				18	1-7-15
				16	0-9-0
				53	0-1-16
				55	1-2-15
				58	0-19-0
				59	0-2-0
				60	1-12-10
				61	1-7-12
				62	0-7-16
				36	0-1-0
				35	0-1-0
				37	1-8-0
				30	0-1-0

का० आ० 4695—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप-लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3899 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की उपधारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करता है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

#### हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	आंवला संग्रामपुर		58	0-0-10
				59	0-7-0
				57	0-3-0
				60	0-18-0
				56	0-0-5
				68	1-16-0
				67	0-2-0
				66	0-1-5
				65	0-3-10

1	2	3	4	5	6
				192	0-0-10
				126	0-10-10
				129	0-17-10
				132	1-3-10
				133	0-11-15
				134	0-5-10
				124	0-0-15
				123	0-14-10
				121	0-14-10
				120	0-11-0
				111	0-2-5
				119	0-0-10
				113	0-18-0
				112	0-13-15
				106	0-0-10
				105	0-7-0
				94	1-3-0
				100	0-18-0
				96	0-0-15
				104	0-1-0

[सं. O-14016/447/85-जी पी]

S.O. 4695.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3899 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (I) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (I) of Section 6 of the said Act the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

#### H.B.J. Pipe line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Sang-rampur	58	0-0-10
				59	0-7-0
				57	0-3-0

1	2	3	4	5	6	उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रिय सरकार में निहित होने के बगैर भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभा बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन का इस तारख को निहित होगा।
				60	0-18-0	
				56	0-0-5	
				68	1-16-0	
				67	0-2-0	
				66	0-1-5	
				65	0-3-10	
				192	0-0-10	
				126	0-10-10	
				129	0-17-10	
				132	1-3-10	
				133	0-11-15	
				134	0-5-10	
				124	0-0-15	
				123	0-14-10	
				121	0-14-10	
				120	0-11-0	
				111	0-2-5	
				119	0-0-10	
				113	0-18-0	
				112	0-13-15	
				106	0-0-10	
				105	0-7-0	
				94	1-3-0	
				100	0-18-0	
				96	0-0-15	
				104	0-1-0	

## अनुसूची

## जिला-बरेली-अगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुन्तोर	राजपुरा	कृतिया	266	0-9-15
				267	0-9-5
				265	0-15-0
				264	0-2-5
				277	0-6-0
				263	1-1-0
				262	0-8-10
				260	0-13-0
				261	0-0-10
				259	0-10-15
				253	0-0-15
				247	0-18-0
				231	1-13-0
				237	0-3-0
				233	0-0-10
				232	1-15-0
				212	1-4-0
				211	0-0-5
				188	0-14-0
				189	0-2-15
				190	0-17-0
				180	1-13-10
				181	0-9-0
				179	0-0-10
				116	0-4-0
				117	0-5-10
				118	1-15-0
				103	0-1-5
				122	1-8-10
				102	0-5-0
				101	0-6-0
				100	0-1-15
				98	0-4-10
				99	0-8-0
				69	0-1-15
				81	0-4-0
				70	0-8-0
				71	0-14-0

[No. O-14016/447/85-GP]

का.आ. 4696.- यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3909 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	6	6
				72	0-10-0					264	0-2-5
				73	0-13-10					277	0-6-0
				79	0-0-10					263	1-1-0
				38/	0-10-15					262	0-8-10
				1088						260	0-13-0
				37	0-5-15					261	0-0-10
				33	0-0-5					259	0-10-15
				30	0-10-0					253	0-0-15
				31	0-6-15					247	0-18-0
				29	0-17-10					231	1-13-0
				28	0-4-15					237	0-3-0
				427	0-5-10					233	0-0-10
				431	0-7-5					232	1-15-0
				432	0-15-0					212	1-4-0
				446	0-10-5					211	0-0-5
				445	0-4-0					188	0-14-0
				444	0-1-15					189	0-2-15
				437	0-2-15					190	0-17-0
				438	0-3-10					180	1-13-10

[सं. O-14016/478/85-जी पी]

S.O. 4696.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3909 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline:

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5
Badaun	Gun-nour	Rajpura Kritiya	266	0-9-15
			267	0-9-5
			265	0-15-0

117	0-5-10
118	1-15-0
103	0-1-5
122	1-8-10
102	0-5-0
101	0-6-0
100	0-1-15
98	0-4-10
99	0-8-0
69	0-1-15
81	0-4-0
70	0-8-0
71	0-14-0
72	0-10-0
73	0-13-10
79	0-0-10
38/1088	0-10-15
37	0-5-15
33	0-0-5
30	0-10-0
31	0-6-15
29	0-17-10
28	0-4-15
427	0-5-10
431	0-7-5
432	0-15-0
446	0-10-5
445	0-4-0
444	0-1-15
437	0-2-15
438	0-3-10

[No. O-14016/478/85-GP]



का० आ० 4697.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3890 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अर्जन आश्रय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निवेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला तहसील पargana गांव गाटा नं. लिया गया रकबा

1	2	3	4	5	6
बरेली	आंबला	आंबला	बिलौरी	408	0-1-10
				409	0-0-10
				458	0-10-0
				457	0-6-0
				456	1-5-0
				459	0-3-10
				462	0-0-5
				463	0-0-5
				464	0-0-15
				465	0-0-15
				466	0-0-15

1	2	3	4	5	6
				467	0-5-0
				468	0-1-10
				455	0-11-0
				469	0-0-15
				471	0-13-15

[सं. O-14016/437/85-जी पी]

S.O. 4697.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3890 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land, Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Awala	Billaury	408	0-1-10
				409	0-0-10
				458	0-10-0
				457	0-6-0
				456	1-5-0
				459	0-3-10
				462	0-0-5
				463	0-0-5
				464	0-0-15
				465	0-0-15
				466	0-0-15
				467	0-5-0
				468	0-1-10
				455	0-11-0
				469	0-0-15
				471	0-13-15

[No. O-14016/437/85-GP]

का०आ० 4698:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का०आ० सं० 3897 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सूक्ष्म प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख की निहित होगी।

#### अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	मोहम्मदपुर पहारी	561	0-7-5
				562	0-2-0
				563	0-6-0
				586	0-14-10
				606	0-0-10
				605	0-4-0
				604	0-10-0
				594	0-13-0
				595	0-11-0
				659	2-8-0
				682	0-6-10

5 6

699	0-12-0
698	0-5-10
710	0-1-5
713	1-7-10
767	1-4-0
786	1-2-15
785	1-4-0

[सं. O-14016/444/85-जी पी]

S.O. 4698.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3897 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

#### SCHEDULE HBJ Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Mohamed	561	0-7-5
				562	0-2-0
			Pur	563	0-6-0
			Pathra	586	0-14-10
				606	0-0-10
				605	0-4-0
				604	0-10-0
				594	0-13-0
				595	0-11-0
				659	2-8-0
				653	0-6-10
				699	0-12-0
				698	0-5-10
				710	0-1-5
				713	1-7-10
				767	1-4-0
				786	1-2-15
				785	1-4-0

[No. O-14016/444/85-GP]

का. आ. 4699.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3892 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रिय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधिन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अथ, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देता है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

#### अनुसूची

#### हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला तहसील परगना गाँव गाँवा सं. लिया गया रकबा

1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	पमारी	69	1-3-0
				62	0-7-0
				61	1-1-0
				31	0-0-15
				29	0-9-0
				28	0-13-0
				32	0-0-10
				36/249	0-0-5
				36	0-17-10
				35	0-16-5
				82	2-14-0
				88	0-2-10
				89	1-10-10
				78	0-0-5
				95	0-0-10

[सं. O-14016/439/85-जो पी]

S.O. 4699.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3892 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Pamari	69	1-3-0
				62	0-7-0
				61	1-1-0
				31	0-0-15
				29	0-9-0
				28	0-13-0
				32	0-0-10
				36/249	0-0-5
				36	0-17-10
				35	0-16-5
				82	2-14-0
				88	0-2-10
				89	1-10-10
				78	0-0-5
				95	0-0-10

[No. O-14016/439/85-GP]

का. आ. 4700.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधिन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3905 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बरेली	आंवला	सन्हा	बाकरगंज	48	0-4-0
				50	0-8-0
				174	0-0-15
				172	0-2-0
				173	0-5-0
				171	0-7-0
				170	0-14-0
				168	0-7-0
				164	0-1-5
				154	0-13-0
				153	0-3-0
				152	0-13-0
				151	0-7-0
				49	0-3-0

[सं. O-14016/441/85-जो पी]

S.O. 4700.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. No. 3905 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government ;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification ;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline ;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### H.B.J. Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala	Sanha	Bahar-ganj	48	0-4-0
				50	0-8-0
				174	0-0-15
				172	0-2-0
				173	0-5-0
				171	0-7-0
				170	0-14-0
				168	0-7-0
				164	0-1-5
				154	0-13-0
				153	0-3-0
				152	0-13-0
				151	0-7-0
				49	0-3-0

[No. O-14016/441/85-GP]

का. डा. 4701.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय को अधिसूचना का. आ. सं. 3940 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस द्वारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा-वरेली-जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	बिश्नौली	बिश्नौली	फतेहपुर	1089	0-5-10
		वीरमपुर		1090	1-3-10
				1091	0-0-15
				1093	0-9-0
				1095	0-4-0
				1111	0-0-15
				1112	0-2-0
				1113	0-7-10
				1114	0-8-10
				1115	0-2-0
				1116	0-4-10
				1117	0-0-15
				1119	0-1-10
				1118	0-10-0
				1128	0-0-15
				1129	0-0-10
				1131	0-1-0
				1136	0-0-10
				1139	0-15-0
				1142	0-1-15
				1141	0-0-5
				1143	1-5-0
				1144	0-3-0
				1145	0-0-8
				1146	0-1-5
				1152	0-0-15
				1165	0-11-0
				1164	0-12-10
				1166	0-0-15
				1167	0-4-10
				1169	0-0-10
				1163	1-1-10
				1170	0-4-0
				1172	0-2-10
				1221	0-9-0
				1222	0-0-5
				1223	0-1-0

1	2	3	4	5	6
				1227	0-1-5
				1226	0-15-15
				1225	0-3-0
				1230	0-1-5
				1231	0-10-0
				1232	0-6-10
				1233	0-1-0
				1234	0-0-10
				1237	0-10-0
				1238	0-0-15
				766	0-3-5
				765	1-3-0
				764	0-0-10
				751	0-9-0
				752	0-0-15
				754	0-1-5
				753	0-8-15
				755	0-4-0
				756	0-0-10
				757	0-0-15
				746	0-0-10
				745	0-0-14
				736	0-2-10
				735	1-4-0
				734	0-2-15
				700	0-0-15
				699	0-1-0
				689	0-12-0
				688	0-11-0
				687	0-3-0
				686	0-13-0
				682	0-18-0
				683	0-0-10
				679	0-0-15
				674	0-15-0
				675	0-0-10
				673	0-12-5
				672	0-9-0
				671	0-1-0
				662	0-3-0
				545	0-15-0
				541	0-19-0
				542	0-1-0
				547	1-6-0
				549	0-3-0
				559	1-5-0
				560	0-2-0

1	2	3	4	5	6	SCHEDULE					
						H.B.J. Gas Pipe line Project					
						Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
						1	2	3	4	5	6
				565	0-15-0	Badaun	Bishau-li	Bishau-li	Fateh-pur	1089	0-5-10
				571	0-3-10					1090	1-3-10
				570	0-3-15				Biram-upr	1091	0-0-15
				569	0-2-10					1093	0-7-0
				227	0-6-0					1095	0-4-0
				586	0-13-1					1111	0-0-15
				590	1-3-15					1112	0-2-0
				588	0-0-10					1113	0-7-10
				224	0-3-0					1114	0-8-10
				225	0-15-0					1115	0-2-0
				222	0-16-10					1116	0-4-10
				221	0-0-5					1117	0-0-15
				223	0-1-0					1119	0-1-10
				216	0-11-0					1118	0-10-0
				215	1-2-0					1128	0-0-15
				214	0-0-10					1129	0-0-10
				213	0-5-0					1131	0-1-0
				209	1-1-0					1136	0-0-10
				210	0-3-0					1139	0-15-0
				208	0-0-10					1142	0-1-15
				207	0-0-15					1141	0-0-5
				203	0-19-0					1143	1-5-0
				202	0-0-15					1144	0-3-0
				200	1-6-10					1145	0-0-8
				201	0-0-10					1146	0-1-5
				526	0-0-10					1152	0-0-15
				498	0-0-5					1165	0-11-0
										1164	0-12-10
										1166	0-0-15
										1167	0-4-10
										1169	0-0-10
										1163	1-1-10
										1170	0-4-0
										1172	0-2-10
										1221	0-9-0
										1222	0-0-5
										1223	0-1-0
										1227	0-1-5
										1226	0-15-15
										1225	0-3-0
										1230	0-1-5
										1231	0-10-0
										1232	0-6-10
										1233	0-1-0
										1234	0-0-10
										1237	0-10-0
										1238	0-0-15
										766	0-3-5
										765	1-3-0
										764	0-0-10

[सं. O-14016/469/85-जी पी]

S.O. 4701.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3940 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				751	0-9-0					222	0-16-10
				752	0-0-15					221	0-0-5
				754	0-1-15					223	0-1-0
				753	0-8-15					216	0-11-0
				755	0-4-0					215	1-2-0
				765	0-0-10					214	0-0-10
				746	0-0-10					213	0-5-0
				745	0-0-15					209	1-1-0
				736	0-2-10					210	0-3-0
				735	1-4-0					208	0-0-10
				734	0-2-15					207	0-0-15
				700	0-0-15					203	0-19-0
				699	0-1-0					202	0-0-15
				689	0-12-0					200	1-6-10
				688	0-11-0					201	0-0-10
				687	0-3-0					526	0-0-10
				686	0-13-0					498	0-0-5
				682	0-18-0						
				683	0-0-10						
				679	0-0-15						
				674	0-15-0						
				675	0-0-10						
				673	0-12-5						
				672	0-9-0						
				671	0-1-0						
				662	0-3-0						
				545	0-15-0						
				541	0-19-0						
				542	0-1-0						
				547	1-6-0						
				549	0-3-0						
				559	1-5-0						
				560	0-2-0						
				565	0-15-0						
				571	0-3-10						
				570	0-3-15						
				569	0-2-10						
				227	0-6-0						
				586	0-13-10						
				590	1-3-15						
				588	0-0-10						
				224	0-3-0						
				225	0-15-0						

[No. O-14016/469/85-GP]

का. आ. 4702:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3941 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

## अनुसूची

## हाजिरा-बरेली-जगदालपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	चक्र नं	क्षेत्रफल बोघा	पुराना गाटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8
बदायूं	बिसौली	इस्लाम नगर	सेमुल्लागंज	314	0-3-0		
				524	0-4-0		
				529	0-3-5	11	0-15-0
				556	0-1-15		

1	2	3	4	5	6	7	8
				199	0-1-0		
				380	0-10-0		
					0-1-0		
				598	0-7-10	7	0-8-0
					0-0-10		
				408	0-1-10	6	0-12-0
				598	0-10-5		
					0-0-5		
				408	0-12-0	5	1-5-15
				163	0-10-10		
				563	0-3-5		
				563	0-4-10	32	0-4-10
				563	0-15-10	34	0-15-15
					0-0-5		
				697	0-1-5		
				640	0-8-0	35	0-13-15
				563	0-3-15		
					0-0-15		
				640	0-2-5	36	0-2-5
				640	0-0-10	42	0-0-10
				640	0-12-15		
				615	0-3-5	41	0-17-5
				386	0-1-5		
				386	0-0-15	40	0-0-15
				615	0-0-15	39	0-15-15
				386	0-15-0		
				386	0-7-0	73	0-7-0

[सं. O-14016/465/85- जी पी]

S.O. 4702.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3941 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has, under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of

user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.



## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Distt	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area	Remarks
1	2	3	4	5	6	7 8 9
Badaun	Bisauli	Islam Nagar	Saifulla-Ganj	314	0-3-0	
				524	0-4-0	
				529	0-3-5	11 0-15-0
				556	0-1-15	
				199	0-1-0	
				380	0-10-0	
					0-1-0	
				598	0-7-10	
					0-0-10	7 0-8-0
				408	0-1-10	6 0-12-0
				598	0-10-5	
					0-0-5	
				408	0-12-0	5 1-5-15
				163	0-10-10	
				563	0-3-5	
				563	0-4-10	32 0-4-10
				563	0-15-10	34 0-15-15
					0-0-5	
				697	0-1-5	
				640	0-8-0	
						35 0-13-15
				563	0-3-15	
					0-0-15	
				640	0-2-5	36 0-2-5
				640	0-0-10	42 0-0-10
				640	0-12-15	
				615	0-3-5	41 0-17-5
				386	0-1-5	
				386	0-0-15	40 0-0-15
				615	0-0-15	
						39 0-15-1
				386	0-15-0	
				386	0-7-0	73 0-7-0

[No. O-14016/465/85-G.P.]

का.अ. 4703.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. अ. सं. 3632 दिनांक 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था,

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

826 GI/85—5

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रिय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में संघीय बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

### अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुन्नौर	असदपुर औरंगाबाद	289	0-5-15	
			294	0-5-0	
			293	0-6-15	
			292	0-5-10	
			291	0-0-10	
			290	0-11-5	
			288	0-4-10	
			295	0-0-15	
			303	0-1-0	
			297	1-2-17	
			298	0-1-15	
			299	1-4-0	
			306	0-0-17	
			310	1-10-0	
			311	0-3-15	
			312	1-1-15	
			338	0-0-18	
			344	0-17-0	
			343	1-2-5	
			346	0-6-0	
			347	0-14-0	
			348	0-1-0	
			349	0-5-0	
			342	0-0-15	
			341	1-2-0	
			340	0-16-0	
			570	0-1-0	
			571	0-10-10	
			556	0-17-0	
			557	0-0-10	
			565	1-10-5	
			564	0-0-15	

S.O. 4703.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3932 dated 17-8-1985 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government.

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification.

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gunnour	Asad-pur	Aurn-gabad	289	0-5-15
				294	0-5-0
				293	0-6-15
				292	0-5-10
				291	0-0-10
				290	0-11-5
				288	0-4-10
				295	0-0-15
				303	0-1-0
				297	1-2-17
				298	0-1-15
				299	1-4-0
				306	0-0-17
				310	1-10-0
				311	0-3-15
				312	1-1-15
				338	0-0-18
				344	0-17-0
				343	1-2-5
				346	0-6-0
				347	0-14-0
				348	0-1-0
				349	0-5-0
				342	0-0-15
				341	1-2-0
				340	0-16-0
				570	0-1-0
				571	0-10-10
				556	0-17-0
				557	0-0-10
				565	1-10-5
				564	0-0-15

का. आ. 4704.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3928 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और, यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्टें दे दी हैं।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्द्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप से घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा बरेली जंगदीश पुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	परगना	गांव	गोटा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुझीर	असदपुर	सुनवर	458	0-9-12
			सराय	454	0-1-10
				457	0-16-0
				463	0-1-0
				464	1-0-0
				448	0-8-0
				447	1-11-4
				447	—
				—	0-2-10
				2356	—
				405	0-12-0
				445	0-7-10
				406	0-10-0
				438	0-7-10
				439	0-7-10
				440	0-19-4
				437	0-1-10
				559	—
				—	0-9-10
				2378	—

1	2	3	4	5	6
				559	0-4-10
				560	0-1-10
				561	0-1-0
				565	1-0-0
				564	0-11-0
				567	0-7-0
				568	0-5-0
				563	0-3-10
				578	0-7-0
				577	1-2-0
				589	0-0-12
				587	0-16-0
				588	0-6-0
				595	0-7-0
				594	1-6-0
				592	0-0-15
				591	0-0-5
				593	1-4-0
				605	0-2-0
				606	0-9-10
				607	0-0-10
				715	—
				—	0-0-12
				2385	—
				1622	1-1-0
				1620	0-17-0
				1621	—
				—	0-8-0
				2388	—
				1621	0-0-10
				1607	1-19-0
				1615	1-4-0
				734	0-0-12
				735	1-0-0
				737	0-3-0
				738	0-14-0
				740	0-3-0
				743	0-2-10
				956	0-5-0
				957	0-8-0
				958	0-5-0
				954	0-14-0
				953	0-2-5
				951	0-9-0
				952	0-1-10

1	2	3	4	5	6
				949	0-8-0
				936	0-0-5
				948	0-6-0
				937	0-8-0
				938	0-1-10
				942	1-11-0
				943	0-1-0
				914	2-15-0
				1130	0-3-0
				1131	2-9-0
				1114	0-12-10
				1134	0-18-0
				1135	0-1-0
				1113	0-11-0
				1106	0-10-0
				1138	0-3-0
				1139	1-0-0
				1105	0-1-10
				1157	1-8-0
				1159	1-2-0
				1175	0-2-0
				1182	0-15-0
				1179	0-0-15
				1181	0-15-0
				1180	0-3-0
				1183	0-4-0
				1137	0-8-0
				917	0-3-0
				462	0-0-10
				588	
					0-0-2
				2389	
				1622	
					0-0-10
				2386	
				1675	0-0-5
				912	0-1-0
				1098	0-0-10
				1174	1-16-15

[सं. O-14016/487/85-जीपी]

S.O. 4704.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3928 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Government;

And, further, whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands, shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Par-gana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gunnour	Asadpur	Sunver Sarai	458	0-9-12
				454	0-1-10
				457	0-16-0
				463	0-1-0
				464	1-0-0
				448	0-8-0
				447	1-11-4
				447	
					0-2-10
				2356	
				405	0-12-0
				445	0-7-10
				406	0-10-0
				438	0-7-10
				439	0-7-10
				440	0-19-4
				437	0-1-10
				559	
					0-9-10
				2378	
				559	0-4-10
				560	0-1-10
				561	0-1-0
				565	1-0-0
				564	0-11-0
				567	0-7-0
				568	0-5-0
				563	0-3-10
				578	0-7-0
				577	1-2-0
				589	0-0-12
				587	0-16-0
				588	0-6-0
				595	0-7-0
				594	1-6-0

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				592	0-0-15				1183	0-4-0	
				591	0-0-5				1137	0-8-0	
				593	1-4-0				917	0-3-0	
				605	0-2-0				462	0-0-10	
				606	0-9-10				588		
				607	0-0-10				2389	0-0-2	
				715					1622		
				2385	0-0-12				2386	0-0-10	
				1622	1-1-0				1675	0-0-5	
				1620	0-17-0				912	0-1-0	
				1621					1098	0-0-10	
					0-8-0				1174	1-16-15	
				2388							
				1621	0-0-10						
				1607	1-19-0						
				1615	1-4-0						
				734	0-0-12						
				735	1-0-0						
				737	0-3-0						
				738	0-14-0						
				740	0-3-0						
				743	0-2-10						
				955	0-5-0						
				957	0-8-0						
				958	0-5-0						
				954	0-14-0						
				953	0-2-5						
				951	0-9-0						
				952	0-1-10						
				949	0-8-0						
				936	0-0-5						
				948	0-6-0						
				937	0-8-0						
				938	0-1-10						
				942	1-11-0						
				943	0-1-0						
				914	2-15-0						
				1130	0-3-0						
				1131	2-9-0						
				1114	0-12-10						
				1134	0-18-0						
				1135	0-1-0						
				1113	0-11-0						
				1105	0-10-0						
				1138	0-3-0						
				1139	1-0-0						
				1105	0-1-10						
				1157	1-8-0						
				1159	1-2-0						
				1175	0-2-0						
				1182	0-15-0				811	1-1-0	
				1179	0-0-15				809	0-1-5	
				1181	0-15-0				810	0-1-0	
				1180	0-3-0				818	0-4-0	

1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
				819	1-2-0					318	0-6-0
				820	0-5-0					319	0-4-0
				821	0-2-0					334	0-2-0
				822	0-0-5					372	0-12-0
				876	0-17-10					371	0-4-0
				873	0-10-15					373	0-12-0
				872	0-5-10					366	1-5-0
				871	0-10-0					374	0-0-5
				850	0-0-10					377	0-11-10
				838	1-11-10					387	0-3-10
				784	0-17-0					388	0-8-10
				789	0-0-5					396	1-2-0
				211	0-1-10					447	0-7-5
				210	0-16-15					443	0-11-5
				215	0-8-10					444	0-0-5
				216	0-12-0					442	0-4-10
				218/						441	0-0-10
				997	0-2-10					437	0-8-10
				218	0-12-0					438	0-2-10
				217	0-15-0					439	0-1-0
				219	0-0-5					476	0-6-0
				220	0-2-0					477	0-1-15
				236	0-1-5					478	0-15-0
				237	0-6-0					376	0-0-5
				235	0-13-0					783	0-0-5
				233	0-0-18					837	0-0-15
				245	0-15-0					386	0-0-10
				244	1-5-15					440	0-0-10
				246	0-1-5						
				248	0-2-10						
				247	0-5-15						
				54	0-1-0						
				41	1-0-15						
				48	0-12-0						
				49	0-5-10						
				50	0-5-0						
				51	0-10-5						
				47	0-10-0						
				262	0-0-12						
				322	0-7-5						
				323	0-12-5						
				325	0-0-10						
				324	0-13-0						
				326	0-0-5						
				321	1-12-0						
				320	0-1-0						

[सं. O-14016/485/85-जीपी]

S.O. 4705.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 3926 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And, whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

**SCHEDULE**  
**H.B.J. Gas Pipe Line Project**

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-nour	Raj-pura	Sajana Ahran	811	1-1-0
				809	0-1-5
				810	0-1-0
				818	0-4-0
				819	1-2-0
				820	0-5-0
				821	0-2-0
				822	0-0-5
				876	0-17-14
				873	0-10-15
				872	0-5-10
				871	0-10-0
				850	0-0-10
				838	1-11-10
				784	0-17-0
				789	0-0-5
				211	0-1-10
				210	0-16-15
				215	0-8-10
				216	0-12-0
				218/997	0-2-10
				218	0-12-0
				217	0-15-0
				219	0-0-5
				220	0-2-0
				236	0-1-5
				237	0-6-0
				235	0-13-0
				233	0-0-18
				245	0-15-0
				244	1-5-15
				246	0-1-5
				248	0-2-10
				247	0-5-15
				54	0-1-0
				41	1-0-15
				48	0-12-0
				49	0-5-10
				50	0-5-0
				51	0-10-5
				47	0-10-0
				262	0-0-12
				322	0-7-5
				323	0-12-5
				325	0-0-10
				324	0-13-0
				326	0-0-5
				321	1-12-0
				320	0-1-0
				318	0-6-0
				319	0-4-0
				334	0-2-0
				372	0-12-0
				371	0-4-0
				373	0-12-0
				366	1-5-0
				374	0-0-5
				377	0-11-10
				387	0-3-10
				388	0-8-10
				396	1-2-0

447	0-7-0
443	0-11-5
444	0-0-5
442	0-4-10
441	0-0-10
437	0-8-10
438	0-2-10
439	0-1-0
476	0-6-0
477	0-1-15
478	0-15-0
376	0-0-5
783	0-0-5
837	0-0-15
386	0-0-10
440	0-0-10

[No. O—14016/485/85-G.P.]

का. 37. 4706.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 50) क धारा 3 क उपधारा (1) के अधिनियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. भा. सं. 3936 तारख 17-8-85 द्वारा केन्द्र य सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सश्रम प्राधिकारों ने उक्त अधिनियम की धारा 6 क उपधारा (1) के अधीन सरकार की रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यतः उक्त अधिनियम की धारा 6 क उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करने हुए केन्द्र य सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूच में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया गया है।

और आगे उस धारा क उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र य सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्र य सरकार में निहित होने के बजाय भारत य गैस प्राधिकरण लि. में सश्रम बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन क. इस तारख को निहित होगा।

**अनुसूची**

**हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट :**

जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवा संख्या	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुप्तगौर	राजपुरा	वहीपुर	55	0-4-10
				57	0-3-10
				56	0-6-0
				63	0-0-10
				64	0-7-5
				65	0-10-0
				66	0-4-0
				72	0-12-10
				71	0-0-15

1	2	3	4	5	6
				67	0-11-0
				70	0-6-0
				82	1-12-18
				81	0-1-10
				85	1-5-0
				87	0-0-12
				88	0-9-7
				89	0-12-12
				172	0-1-18
				182	0-1-0
				183	0-8-14
				184	0-0-15
				211	1-11-12
				212	0-19-0
				208	0-10-0
				214	0-1-12
				218	1-4-0
				251	0-5-17
				252	0-3-12
				260	0-13-4
				259	1-0-8
				257	0-3-13
				258	0-6-18
				261	0-0-15
				268	0-5-5
				269	0-15-0
				270	0-12-0
				272	0-1-0
				274	0-3-0
				271	0-14-0
				340	0-18-0
				341	1-1-8
				343	2-3-0
				345	0-12-0
				368	0-1-10

[सं. O-14016/484/85-जि. पं.]

S.O. 4706.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3935 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt	Teshil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-	Rajpur	Wahi-	55	0-4-10
	nour		pur	57	0-3-10
				56	0-6-0
				63	0-0-10
				64	0-7-5
				65	0-10-0
				66	0-4-0
				72	0-12-10
				71	0-0-15
				67	0-11-0
				70	0-6-0
				82	1-12-18
				81	0-1-10
				85	1-5-0
				87	0-0-12
				88	0-9-7
				89	0-12-12
				172	0-1-18
				182	0-1-0
				183	0-8-14
				184	0-0-15
				211	1-11-12
				212	0-19-0
				208	0-10-0
				214	0-1-12
				218	1-4-0
				251	0-5-17
				252	0-3-12
				260	0-13-4
				259	1-0-8
				257	0-3-13
				258	0-6-18
				261	0-0-15
				268	0-5-5
				269	0-15-0
				270	0-12-0
				272	0-1-0
				274	0-3-0



1	2	3	4	5	6
				271	0 14 0
				340	0 18 0
				341	1 1 8
				343	2 3 0
				345	0 12 0
				368	0 1 10

[No. O-14016/484/85-G.P.]

का. आ. 4707.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3912 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के रजिस्ट्रार भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हाजिरा बरेली जगदीशपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव	गांवा संख्या	नियोजित गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुझीर	असदपुर	कलहा	744	0-9-10
				743	0-5-0
				742	0-1-10
				741	0-11-0
				747	0-6-0
				746	0-10-0

[सं. O-14016/453/85-जीपी.]

S.O. 4707.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3912 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vest on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-nour	Asad-pur	Kalha	744	0-9-10
				743	0-5-0
				742	0-1-10
				741	0-11-0
				747	0-6-0
				746	0-10-0

[No. O-14016/453/85-G.P.]

का. आ. 4708.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. सं. 3918 तारीख 17-7-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः मक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्णय किया है।

अब, अब: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा पदत यन्त्रि का प्रयोग करने हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाना है ।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को ग्राह्य होगा ।

#### अनुसूची

#### हार्जिग अरेला जमदीनपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला	तहसील	पार्गना	गांव	प्लॉट संख्या	निर्दिष्ट किया गया रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गन्धी	अमरपुर	मिरौलिया	172	0-4-10
				179	2-3-4
				181	0-5-0
				180	0-0-15
				178	0-4-5
				177	0-0-5
				176	0-16-10
				184	0-0-15
				188	1-4-0
				190	0-19-17
				189	1-0-0
				191	0-12-10
				192	0-0-10
				193	0-5-0
				159	0-6-0
				153	0-5-0
				155	1-9-0
				156	1-8-0
				157	0-0-5
				124	0-4-10
				74	0-0-10
				73	0-7-5
				71	3-10-6
				62	0-1-0
				63	0-0-8
				70	0-0-8
				69/1	0-10-0
				69/2	0-16-5
				68	0-1-0

S.O. 4708.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3918 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has, under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipe line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area in Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-	Asad-	Sirau-	172	0-4-10
	nour	pur	liya	179	2-3-4
				181	0-5-0
				180	0-0-15
				178	0-4-5
				177	0-0-5
				176	0-16-10
				184	0-0-15
				188	1-4-0
				190	0-19-17
				189	1-0-0
				191	0-12-10
				192	0-0-10
				193	0-5-0
				159	0-6-0
				153	0-5-0
				155	1-9-0
				156	1-8-0
				157	0-0-5
				124	0-4-10
				74	0-0-10
				73	0-7-5
				71	3-10-6
				62	0-1-0
				63	0-0-8
				70	0-0-8
				69/1	0-10-0
				69/2	0-16-5
				68	0-1-0

का० आ० 4709.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3919 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है ;

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है ;

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख का निहित होगा।

अनुसूची

हार्दिक-बरेली-अमदापुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट

जिला तहसील पार्गना गांव गाटा संख्या विद्या गया रकबा

1	2	3	4	5	6
बदायूँ	गुआँर	अमदापुर	जयसमनगर	269	0-6-0
				302	1-2-15
				306	0-13-0
				307	0-12-0
				308	1-4-7
				310	0-7-5
				311	0-6-0
				313	0-0-10
				315	1-0-7
				327	0-14-0
				328	0-4-0
				597	0-10-0
				598	0-4-0
				322	0-2-6

[गं. O-11016/464/85-जा.पो.]

S.O. 4709.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3919 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline ;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances

## SCHEDULE

### H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Dist.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-	Asad-	Jairam	269	0-6-0
	neur	pur	Nagar	302	1-2-15
				306	0-13-0
				307	0-12-0
				308	1-4-7
				310	0-7-5
				311	0-6-0
				313	0-0-10
				315	1-0-7
				327	0-14-0
				328	0-4-0
				597	0-10-0
				598	0-4-0
				322	0-2-6

[No. O-14016/464/85-GP]

का० आ० 4710.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 3898 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था ;

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है :

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाना है :

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

#### अनुसूची

जिल्ला बरेली जगदणपुर प			निर्दिष्ट प्रोजेक्ट ।	
जिल्ला तहसील परगना गांव गा			ख्या किया गया	
			रकबा	
			(एकड़ में)	
1	2	3	5	6
बरेली आबला सुल्हा कपोला				
गादो			808	0-5-0
			929	1-17-10
			828	0-5-0
			813	0-0-5
			827	0-1-5
			826	0-19-10
			847	0-0-5
			846	0-4-10
			845	0-2-12
			736	1-7-5
			737	0-0-5
			716	0-11-18
			719	0-4-10
			722	0-2-0
			721	0-17-0
			720	0-9-10
720/1116			0-0-5	

644	0-18-15
575	0-14-15
577	0-0-5
576	0-2-5
578	0-0-15
579	0-11-10
564	0-5-15
563	0-1-0
565	0-5-15
566	0-1-0
561	0-0-15
560	1-3-10
558	0-1-5
558/1126	0-0-15
545	0-1-15
557	0-12-5
547	0-2-5
548	0-3-0
549	0-9-15
556	0-11-15
550	0-2-10
551	0-1-10
500	0-16-10
552	0-1-0
499	0-10-10
458	0-0-15
457	0-0-15
425	0-14-10
426	1-3-10
423	0-4-0
427	0-6-0
428	0-9-15
429	0-11-15
341	0-2-0
343	0-12-10
330	0-6-15
326	0-1-10
325	0-3-15
307	0-1-0
308	0-12-10
553	0-1-5

[सं. O-14016/416/85-जी.पी.]

S.O. 4710.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3898 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the

Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land specified in the Schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bareilly	Awala Sanha	Kyona	808	0-5-0	
		Shadipur	829	1-17-10	
			828	0-5-0	
			813	0-0-5	
			827	0-1-5	
			826	0-19-10	
			847	0-0-5	
			846	0-4-10	
			845	0-2-12	
			736	1-7-5	
			737	0-0-5	
			716	0-11-18	
			719	0-4-10	
			722	0-2-0	
			721	0-17-0	
			720	0-9-10	
			720/1116	0-0-5	
			644	0-18-15	
			575	0-14-15	
			577	0-0-5	
			576	0-2-5	
			578	0-0-15	
			579	0-14-10	
			564	0-5-15	
			563	0-1-0	
			565	0-5-15	
			566	0-1-0	
			561	0-0-15	
			560	1-3-10	
			558	0-1-5	

1	2	3	4	5	6
				558/1126	0-0-15
				545	0-1-15
				557	0-12-5
				547	0-2-5
				548	0-3-0
				549	0-9-15
				556	0-11-15
				550	0-2-10
				551	0-1-10
				500	0-16-10
				552	0-1-0
				499	0-10-10
				458	0-0-15
				457	0-0-15
				425	0-14-10
				426	1-3-10
				423	0-4-0
				427	0-6-0
				428	0-9-15
				429	0-11-15
				341	0-2-0
				343	1-12-10
				330	0-6-15
				326	0-1-10
				325	0-3-15
				307	0-1-0
				308	0-12-10
				553	0-1-5

[No. O-14016/446/85-GP]

का.आ. 4711:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3934 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा मक्षम (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप-

लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमिओं में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

हजिरा बरेली जगदीशपुर लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	गांव गाटा सं.	लिया गया रकबा
1	2	3	4	5
बदायूं	गुल्लार	असदपुर	मालपुर	69
				61
				59
				58
				32
				31
				29
				30
				33
				34
				35
				36
				27
				26
				25
				38
				46
				45
				41
				42
				43
				40
				44

[सं. O-14016/470/85-जी.पी.]

S.O. 4711.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3934 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquired the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall in read of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

### H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Area No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Badaun	Gun-	Asadpur	Malpur	60	0-14-0
	noure			61	0-7-5
				59	0-9-0
				58	0-2-10
				32	0-3-15
				31	0-3-5
				29	0-0-15
				30	0-0-5
				33	0-0-18
				34	0-3-0
				35	0-2-0
				36	0-7-16
				27	0-0-16
				26	0-4-0
				25	0-2-10
				38	0-0-18
				46	0-0-5
				45	0-4-10
				41	0-8-5
				42	0-9-12
				43	0-10-1
				40	0-4-0
				44	0-0-5

[No. O-14016/470/85-GP]

का. आ. 4712.—यहां पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3938 तारीख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे, यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अभिज्ञ करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार वाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में, घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस लाइन प्रोजेक्ट।

जिला तहसील पारगना गांव गाटा संख्या लिया गया					
					रकबा
1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुझीर	रजपुरा	भकरोली	539	0-12-0
				541	0-2-8
				542	0-11-0
				543	0-6-0
				540	0-1-4
				536	0-7-5
				670	0-2-8
				683	1-2-19
				684	0-10-15
				800	0-7-0
				790	1-16-8
				801	0-0-12
				802	0-7-18
				803	0-18-4
				804	1-4-15
				805	1-4-2
				806	0-0-15
				807	0-7-5
				819	0-2-8
				923	0-2-8
				922	0-6-1

1	2	3	4	5	6
				917	0-19-19
				916	0-3-13
				918	0-0-10
				915	0-8-10
				883	0-13-7
				911	0-7-18
				884	0-0-12
				910	0-13-19
				904	1-4-0
				903	0-0-14
				894	0-16-0
				893	0-15-19
				892	0-9-1
				891	0-8-10
				857	1-2-0
				856	0-6-10

[स. O-14016/479/85-जी.पी.]

S.O. 4712.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3938 dated 17-8-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to require the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### H.B.J. Gas Pipe Line Project.

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Areae Acquired
1	2	3	4	5	6
Bodaun	Gun-nour	Rojpura	Bhakrauly	539	0-12-0
				541	0-2-8
				542	0-11-0
				543	0-6-0

1	2	3	4	5	6
					540
					636
					670
					683
					684
					800
					790
					801
					802
					803
					804
					805
					806
					807
					819
					923
					922
					917
					916
					918
					915
					883
					911
					884
					910
					904
					903
					894
					893
					892
					891
					857
					856

[N. O-14016/479/85-GP]

का. घा. 4713:—यत् पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (मन) में उपयोग के अधिकार का अधिनियम, 1962 (1962 का 30) का धारा 3 का उपधारा (1) के अधिनियम भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का अधिसूचना का. घा. सं. 3910 तारख 17-8-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यत्: सख्त प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम का धारा 6 की उप-धारा (1) के अधिनियम सरकार को रिपोर्ट दे डी है।

और आगे यत्: केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, यत्: उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रवर्तन शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उप-धारा के उपधारा (4) द्वारा प्रवर्तन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्विण रती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारत गैस प्राधिकरण लि. में सभ बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन के इस तारख को निहित होगा।

## अनुसूची

हाजिरा-वरेली-जगदीगपुर पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला नदसीन परगना गांव गाटा सं. लिया गया

रकबा

1	2	3	4	5	6
बदायूं	गुन्नीर	अजयपुर	ब्रमनपुर	2	0-16-15
				3	1-10-0
				4	0-0-15
				5	0-1-0
				76	0-3-0
				77	1-4-0
				6	0-7-0

[सं. O-14016/476/85-जी.पी.]

S.O. 4713.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 3910 dated 17-8-85 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from encumbrances.

## SCHEDULE

## H.B.J. Gas Pipe Line Project

Distt.	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Bodaun	Gun-	Asod-	Bam-	2	0-16-15
	nour	pur	man	3	1-10-0
			Pur	4	0-0-15
				5	0-1-0
				76	0-3-0
				77	1-4-0
				6	0-7-0

No. O-14016/476/85-GP]



का. प्रा. 4714.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय, की अधिसूचना का. प्रा. सं. 2589 तारीख 30-5-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिये अर्जित करने का अपना आणख्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिये एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

हाजिरा-बरेली-जगदीशपुर गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट।

जिला	तहसील	परगना	ग्राम गाटा संख्या	अर्जित रकबा
				एकड़ में
1	2	3	4	5
शाहजहाँपुर	सदर	जमौर	धरनी	180 — 15
			धरमपुर	185 — 13
				186 — 03
				187 — 11
				188 — 03
				190 — 08
				191 — 12
				192 — 05
				195 1 25
				197 — 02
				209 — 02
				212 — 05
				213 — 15
				223 — 01
				224 — 30
				225 — 14
				226 — 30
				229 — 30
				230 — 38
				233 — 30

S.O. 4714.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 2589 dated 30-5-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from encumbrances.

#### SCHEDULE

##### H.B.J. Gas Pipe Line Project

District	Tehsil	Paigana	Village	Plot No.	Area Acquired
1	2	3	4	5	6
Shah-Jahan Pur	Sadar	Jamaur	Dharni-dharpur	180	— 15
				185	— 13
				186	— 03
				187	— 11
				188	— 03
				190	— 08
				191	— 12
				192	— 05
				195	1 25
				197	— 02
				209	— 02
				212	— 05
				213	— 15
				223	— 01
				224	— 30
				225	— 14
226	— 30				
229	— 30				
230	— 38				
233	— 30				

का. प्रा. 4715 :—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का. प्रा. सं. 2719 तारीख 25-8-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार का पाइपलाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना वाह्य घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

अनुसूची

एच. बी. ज. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम गोपालपुर		तहसील ईशागढ़ जिला-गुना राज्य (म. प्र.)
अनु. क्र.	खसरा नं.	उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)
1.	162	0.157
2.	57	0.021
3.	161	0.209
4.	159	0.052
5.	37	0.470
6.	38	0.010
7.	35	0.002
8.	39	0.021
9.	41	0.115
10.	36	0.314
11.	42	0.021
12.	47	0.010
13.	45	0.491
14.	17	0.146
15.	55	0.115
16.	15	0.021
17.	14	0.512
18.	13	0.428
19.	61	0.438
20.	62	0.355
21.	63	0.173
22.	163	0.052

4.133

[सं. ऑ-14016/92/84-जी.पी.]

S.O. 4715.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum, S.O. 2719 dated 25-8-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under Sub-Section (1) of Section 6 of the said Act. submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

### HBJ Gas Pipe Line Project

Village:Gopalur Tehsil:Isagarh District:Guna (M.P.)

S. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectares.
1. 162	0-157
2. 57	0-021
3. 161	0-209
4. 159	0-052
5. 37	0-470
6. 38	0-010
7. 35	0-002
8. 39	0-021
9. 41	0-115
10. 36	0-314
11. 42	0-021
12. 47	0-010
13. 45	0-491
14. 17	0-146
15. 55	0-115
16. 15	0-021
17. 14	0-512
18. 13	0-428
19. 61	0-438
20. 62	0-355
21. 63	0-173
22. 163	0-052

Total Area

4-133

[No. O-14016/92/84-GP]

का. भा. 4716.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1982 (1982 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की अधिसूचना का. भा. सं. 3686 तारीख 17-11-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः नक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिर्देश किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि. में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

शामरमड़ा तहसील चाचोड़ा जिला गुना राज्य (म. प्र.)

अनु. खसरा नं. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टेर्स में)

1. 120/1	0.031
2. 122	0.125
3. 127/1	0.941
4. 99/2	0.068
5. 99/1	0.668
6. 100	0.031
7. 95/1	0.110
8. 94/1	0.366
9. 82/1	0.345
10. 79	0.314
11. 44/1	0.052
12. 61	0.177
13. 1/172/1	0.209
14. 1/1	0.627
कुल क्षेत्रफल	3.464

[मं. ओ-14016/134/84-जी.पी.]

S.O. 4716.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Energy (Deptt. of Petroleum) S.O. 3636 dated 17-11-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land), Act 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

#### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Village: Ramoda, Tehsil: Chachoda, Distt: Guna (M.P.)

S. Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1. 120/1	0.031
2. 122	0.125
3. 127/1	0.941
4. 99/2	0.068
5. 99/1	0.668
6. 100	0.031
7. 95/1	0.110
8. 94/1	0.366
7. 82/1	0.345
10. 79	0.314
11. 44/1	0.052
12. 61	0.177
13. 1/172/1	0.209
14. 1/1	0.627

Total Area 3.464

[No. O-14016/134/84—GP]

का. भा. 4717.—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय (पेट्रोलियम विभाग) की

अधिसूचना का०आ०सं० 880 तारीख 2-3-85 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा में प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

#### अनुसूची

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम रिछावर तहसील: दतिया जिला—दतिया, राज्य (मध्य प्रदेश)

अनु. क्र. खसरा नं. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर में)

1.	844	0.005
2.	845	0.640

योग:—कुल क्षेत्रफल 0.645

[सं. ओ-14016/81/85-जी. पी.]

S.O. 4717.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 880 dated 2-3-85 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

#### SCHEDULE

##### H.B.J. Gas Pipe Line Project

Village : Richhwar Tehsil : Datia Distt. : Datia.

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1.	844	0.005
2.	845	0.640
Total Area		0.645

[No. O-14016/81/85—GP]

का० आ० 4718:—यतः पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना का० आ० सं० 4122 तारीख 1-12-84 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग के अधिकार को पाइप लाइनों को बिछाने के लिए अर्जित करने का अपना आशय घोषित कर दिया था।

और यतः सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सरकार को रिपोर्ट दे दी है।

और आगे यतः केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार अर्जित करने का विनिश्चय किया है।

अब, अतः उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा घोषित करती है कि इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए एतद्वारा अर्जित किया जाता है।

और आगे उस धारा की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्देश

देती है कि उक्त भूमियों में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय भारतीय गैस प्राधिकरण लि० में सभी बाधाओं से मुक्त रूप में घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा।

एच. बी. जे. गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट

ग्राम : सोजना : तहसील गुना जिला : गुना, राज्य (मध्य प्रदेश)

अनुसूची

अनु.क्र. खसरा नं. उपयोग अधिकार अर्जन का क्षेत्र (हेक्टर्स में)		
1	2	3
1.	51	0.031
2.	50	0.051
3.	48/3	0.219
4.	48/2/ख	0.051
5.	47/2	1.117
6.	43	0.166
7.	58/109/2	0.061
8.	58/109/1	0.105
9.	58/109/3	0.073
10.	91	0.575
11.	90	0.084
12.	96	0.041
13.	86	0.314
14.	93/1	0.366
15.	93/2	1.913
16.	95	0.418
17.	47/1	0.555
18.	58/109/4	0.021

कुल योग : क्षेत्रफल 6.161

[सं. O-14016/340/84--जीपी]

एम. एम्. श्रीनिवासन, उप सचिव

S.O. 4718.—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum S.O. 4122 dated 1-12-84 under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to that notification for purpose of laying pipeline;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government;

And further whereas the Central Government has, after considering the said report, decided to acquire the right of user in the lands specified in the schedule appended to this notification;

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said lands specified in the schedule appended to this notification hereby acquired for laying the pipeline;

And further in exercise of power conferred by sub-section (4) of that section, the Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of vesting in Central Government vests on this date of publication of this declaration in the Gas Authority of India Ltd. free from all encumbrances.

## SCHEDULE

H.B.J. Gas Pipe Line Project

Village : Sojana, Tehsil : Guna, Distt. Guna.

S. No.	Survey No.	Area to be Acquired for R.O.U. in Hectare
1	2	3
1.	51	0.031
2.	50	0.051
3.	48/3	0.219
4.	48/2/ख	0.051
5.	47/2	1.117
5.	43	0.166
7.	58/109/2	0.061
8.	58/109/1	0.105
9.	58/109/3	0.073
10.	91	0.575
11.	90	0.084
12.	96	0.041
13.	86	0.314
14.	93/1	0.366
15.	93/2	1.913
16.	95	0.418
17.	47/1	0.555
18.	58/109/4	0.021
Total Area		6.161

[No. 0-14016/340/84--GP]

M.S. SRINIVASAN, Dy. Secy.

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

आदेश

का०आ० 4719--विकास परिपद् (प्राक्रियात्मक नियमावली) 1952 के नियम 2, 4 और 5 के साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में भारत सरकार के आदेश का०आ० सं० 5/15/85-सीमेंट दिनांक 30 मई, 1985 में आंशिक संशोधन करते

हुए आदेश में विद्यमान क्रमांक 10 को क्रमांक 11 करने के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि को जायेगी तथा विद्यमान क्रमांक 11 से आगे तक को संख्याओं को क्रमांक 12 से लेकर क्रमांक 25 तक समाप्त होने वाली संख्याओं को पुनः संख्यांकित किया जायेगा :—

“क्रमांक 11—श्री एन.एस. सेख सरिया, प्रबंध निदेशक, मं० गुजरात अम्बुजा सीमेंट लि०, बम्बई।”

[सं० 5/15/85-सीमेंट]

ई०वी०एल०प्रसादाराव, अवर सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY & COMPANY AFFAIRS  
(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 13th September, 1985

ORDER

S.O. 4719.—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) read with rules 2, 4 & 5 of the Development Councils (Procedural Rules) 1952, and in partial modification of the order of the Govt. of India in the Ministry of Industry & Company Affairs (Department of Industrial Development) S.O. No. 5/15/84-Cement dated the 30th May, 1985, the following entry will be made in the order after the existing S. No. 10 as S. No. 11 and the existing S. No. 11 onwards will be re-numbered as S No. 12 etc. ending with S. No. 25:—

“S. No. 11—Shri N. S. Sekhsaria, Managing Director, M/s. Gujarat Ambuja Cement Ltd. Bombay.”

[No. 5/15/85-Cem.]

E. V. L. PRASADA RAO, Under Secy.

इस्पात खान और कोयला मंत्रालय  
(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 1985

क्र०आ० 4720—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिये प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप नियम (4) के अनुसरण में इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय, कोयला विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित कार्यालयों जिनके 80% या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, को उक्त उप नियम के प्रयोजनों के लिये अधिभूषित करती है :—

1. कोयला खान कल्याण आयुक्त कार्यालय, (मुख्यालय) धनबाद।
2. कार्यपालक अभियन्ता नं० 1 का कार्यालय, कोयला खान कल्याण कार्य, धनबाद।
3. कल्याण प्रशासक कार्यालय (परिवार कल्याण) कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद।
4. मुख्य मेलेरिया अधिकारी का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद।
5. मेलेरिया अधिकारी का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद।
6. मेलेरिया अधिकारी का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, धनबाद।

7. सहायक कल्याण आयुक्त का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, भुल्ला, धनबाद।

8. कल्याण प्रशासक का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, हजारीबाग।

9. मेलेरिया अधिकारी का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, हजारीबाग।

10. उप-कल्याण आयुक्त का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, जबलपुर (म०प्र०)

11. कल्याण प्रशासक का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, शहडोल।

12. कल्याण प्रशासक का कार्यालय, कोयला खान कल्याण संस्था, जूनारदेव, छिन्दवाड़ा, (म०प्र०)

13. कल्याण प्रशासन का कार्यालय, उड़ीसा कोयला क्षेत्र, तालचर, उड़ीसा।

[सं० ई०-11016/19/85-हिंदी]

रमेश कुमार, निदेशक

MINISTRY OF STEEL, MINES & COAL  
(Department of Coal)

New Delhi, the 12th September, 1985

S.O. 4721.—In pursuance of sub-rule (4) of rule 10 of the Official Language (Use of Official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notify the following offices under the Ministry of Steel, Mines & Coal, Department of Coal, the 80 per cent or more staff whereof have acquired working knowledge of Hindi, for the purpose of the said sub-rule :—

1. Office of the Coal Mines Welfare Commissioner (Hqrs.) Dhanbad.
2. Office of the Executive Engineer No. 1, Coal Mines Welfare Works, Dhanbad.
3. Office of the Welfare Administrator (Family Welfare), Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad.
4. Office of the Chief Malaria Officer, Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad.
5. Office of the Malaria Officer, Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad.
6. Office of the Filaria Officer, Coal Mines Welfare Organisation, Dhanbad.
7. Office of the Assistant Welfare Commissioner, Coal Mines Welfare Organisation, Bhulli, Dhanbad.
8. Office of the Welfare Administrator, Coal Mines Welfare Organisation, Hazari.bagh.
9. Office of the Malaria Officer, Coal Mines Welfare Organisation, Hazaribagh.
10. Office of the Deputy Welfare Commissioner, Coal Mines Welfare Organisation, Jabalpur (M.P.).
11. Office of the Welfare Administrator, Coal Mines Welfare Organisation, Shahdol.
12. Office of the Welfare Administrator, Coal Mines Welfare Organisation, Junardev, Chhindwada, (M.P.).
13. Office of the Welfare Administrator, Orissa Coal-fields, Talcher Orissa.

[F. No. E-11016/19/85-Hindi]  
RAMESH KUMAR, Director.

(नई दिल्ली, 16 सितम्बर 1985)

का. आ. 1731:—केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि इससे अपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित भूमि में कोयला अभि-  
प्राप्त किये जाने की संभावना है;

अतः केन्द्रीय सरकार कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 4 की  
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस क्षेत्र में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती  
है;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के रेखांक खंड सी.-1 (ई.) III/डी आर/295-285 तारीख 20 फरवरी,  
1985 का निरीक्षण, वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (राजस्व अनुभाग) कोयला एस्टेट सिविल लाइन्स नागपुर-440001 के कार्यालय  
में या कलक्टर बिलासपुर (मध्य प्रदेश) के कार्यालय में अथवा कोयला नियंत्रक काउन्सिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में  
किया जा सकता है।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (7) में  
निर्दिष्ट सभी नक्शों, चार्टों और अन्य दस्तावेजों को, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर राजस्व अधिकारी  
वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, कोयला एस्टेट, सिविल लाइन्स, नागपुर- 440001 को भेजेगा।

## अनुसूची

## पाली ब्लाक

## कोरवा कोयला क्षेत्र

## जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)

क्रम सं.	ग्राम	तहसील	हल्का	खेबट	जिला	क्षेत्र हैक्टरों में	टिप्पणियां
1.	बोड़ा	कटघोरा	30	53	बिलासपुर	1106.350	पूर्ण
2.	नोनबिरा	"	30	43	"	1468.361	"
3.	उड़ता	"	30	43	"	964.559	"
4.	छिन्दपानी	"	30	असर्वेक्षित	"	1244.529	"
5.	वांथाखार	"	28	76	"	642.490	"
6.	तुनेरा	"	27	75	"	1298.216	"
7.	पुटा	"	30	44	"	1242.076	"
8.	करतला	"	26	78	"	1310.274	"
9.	घोरागाछा	"	27	39	"	673.593	"
10.	तेन्दूमाठा	"	26	76	"	154.131	"
11.	गणेशपुर	"	26	असर्वेक्षित	"	171.738	"
12.	वनबांधा	"	27	36	"	423.566	"
13.	डोंमानाला	"	26	75	"	445.302	"
14.	दमिया	"	25	75	"	456.228	"
15.	रंगोल	"	25	40	"	315.802	"
16.	डुमखछार	"	25	41	"	674.930	"
17.	मादन	"	24	42	"	539.406	"
18.	पाली	"	25	65	"	263.857	"
19.	सराईपाली	"	25	67	"	311.388	"
20.	सेला	"	24	44	"	528.784	"

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	केरासिरीया	कटघोरा	24	64	बिलासपुर	431.946	पूर्ण
22.	बुड़बुड़	"	25	66	"	684.241	"
23.	राहाडीह	"	25	68	"	236.458	"
24.	तेलावार	"	25	69	"	76.444	"
25.	सेमरकोछार	"	25	70	"	192.231	"
26.	मुनगाडीह	"	26	71	"	489.773	"
27.	हुकुपधरा	"	25	62	"	793.391	"
28.	पोंडीकला	"	23	60	"	1560.998	"
29.	पुलासीकला	"	24	46	"	462.581	"
30.	नवापारा	"	24	45	"	259.509	"
31.	नानपुलाली	"	24	63	"	382.000	"

कुल क्षेत्र : 19795.152 हेक्टर (लगभग)

या 48914.86 एकड़ (लगभग)

सीमा वर्णन :

क-ख रेखा, बिन्दु "क" से प्रारम्भ होती है और पोंडीकला, पुलासीकला, नवापारा, सेला, मादन ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख-ग रेखा, हुमरकोछार ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-घ रेखा, हुमरकोछार, बनबांधा ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ-साथ और बनबांधा ग्राम की पूर्वी सीमा के भी साथ-साथ जाती है और फिर घोरामाठा, तुनेरा, बांधाखार, नीनधिरा ग्रामों की उत्तरी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

घ-ङ रेखा, नोनविरा, चौड़ा ग्रामों की पूर्वी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "ङ" पर मिलती है।

ङ-च-छ रेखा, चौड़ा, छिन्दपानी, पुटा, करतला, गणेशपुर, डोंगानाला, मुनगाडीह, सेमरकोछार, हुकुपधरा, पोंडीकला ग्रामों की दक्षिणी सीमा के साथ-साथ जाती है और बिन्दु "छ" पर मिलती है।

छ-क रेखा, पोंडीकला ग्राम की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ जाती है और आरम्भिक बिन्दु "क" पर मिलती है।

[फा. सं.-43015/13/85-सीए]

ममय मिह, जवर सचिव

New Delhi, the 16th September, 1985

S.O. 4721.—Whereas it appears to the Central Government that coal is likely to be obtained from the lands mentioned in the Schedule hereto annexed;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for coal therein :

The plan bearing No. C-I(E)/III/DR/295—285 dated the 20th February 1985 of the area covered by this notification can be inspected at the Office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section), Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 or at the Office of the Collector, Bilaspur (Madhya Pradesh) or at the Office of the Coal Controller, 1, Council House Street, Calcutta.

All persons interested in the lands covered by this notification shall deliver all maps, charts and other documents referred to in sub-section (7) of section 13 of the said Act to the Revenue Officer, Western Coalfields Limited, Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 within ninety days from the date of publication of this notification.



THE SCHEDULE  
PALI BLOCK  
KORBA COALFIELDS  
DISTRICT BILASPUR (MADHYA PRADESH)

Serial Number	Village	Tahsil	Halka number	Khewat number	District	Area in hectares	Remarks
1.	Chorha	Katghora	30	53	Bilaspur	1106.350	Full
2.	Nonbira	Katghora	30	42	Bilaspur	1468.361	Full
3.	Urtā	Katghora	30	43	Bilaspur	964.559	Full
4.	Chhindpani	Katghora	30	Unsur-veyed	Bilaspur	1244.529	Full
5.	Bandhakhar	Katghora	28	76	Bilaspur	642.490	Full
6.	Nunera	Katghora	27	75	Bilaspur	1298.216	Full
7.	Putā	Katghora	30	44	Bilaspur	1242.076	Full
8.	Kartala	Katghora	26	78	Bilaspur	1310.274	Full
9.	Dhaurabhatha	Katghora	27	39	Bilaspur	673.593	Full
10.	Tendubhatha	Katghora	26	76	Bilaspur	154.131	Full
11.	Ganeshpur	Katghora	26	Unsur-veyed	Bilaspur	171.738	Full
12.	Banbandha	Katghora	27	36	Bilaspur	413.566	Full
13.	Donganala	Katghora	26	75	Bilaspur	445.302	Full
14.	Damia	Katghora	25	75	Bilaspur	456.228	Full
15.	Rangole	Katghora	25	40	Bilaspur	315.802	Full
16.	Dumarkachhar	Katghora	25	41	Bilaspur	674.930	Full
17.	Madan	Katghora	24	42	Bilaspur	539.406	Full
18.	Pali	Katghora	25	65	Bilaspur	263.857	Full
19.	Saraipali	Katghora	25	67	Bilaspur	311.388	Full
20.	Saila	Katghora	24	44	Bilaspur	528.784	Full
21.	Kerajhiria	Katghora	24	64	Bilaspur	431.946	Full
22.	Budbud	Katghora	25	66	Bilaspur	684.241	Full
23.	Rahadih	Katghora	25	68	Bilaspur	236.458	Full
24.	Telapar	Katghora	25	69	Bilaspur	76.444	Full
25.	Semarkachhar	Katghora	25	70	Bilaspur	192.231	Full
26.	Mungadih	Katghora	26	71	Bilaspur	489.773	Full
27.	Dhukupathra	Katghora	25	62	Bilaspur	793.391	Full
28.	Pondikala	Katghora	23	60	Bilaspur	1560.998	Full
29.	Pulalikala	Katghora	24	46	Bilaspur	462.581	Full
30.	Nawapara	Katghora	24	45	Bilaspur	259.509	Full
31.	Nanpulali	Katghora	24	63	Bilaspur	382.000	Full
Total Area :						19795.152 hectares (approximately)	
or						48914.81 acres (approximately)	

## Boundary description :

A-B Line starts from 'A' and passes along the northern boundary of villages Pondikala, Pulalikala, Nawapara, Saila, Madan and meets at point 'B'.

- B-C Line passes along the western boundary of village Dumarkachhar and meets at point 'C'.
- C-D Line passes along the northern boundary of villages Dumarkachhar, Banbandha and also eastern boundary of village Banbandha and then proceeds along the northern boundary of villages Dhaura-bhatha, Nunera, Bandhakhar, Nonbira and meets at point 'D'.
- D-E Line passes along the eastern boundary of villages Nonbira, Chorha and meets at point 'E'.
- E-F-G Line passes along the southern boundary of villages Chorha, Chhindpani, Puta, Kartala, Ganeshpur, Donganala, Mungadih, Semarkochhar, Dhukupathra, Pondikala and meets at point 'G'.
- G-A Line passes along the western boundary of village Pondikala and meets at starting point 'A'.

[F. No. 43015/13/85-CA]

SAMAY SINGH, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

New Delhi, the 18th September, 1985

## CORRIGENDUM

S.O.4722.—In the Notification No. V-17012/1/85-ME(PG) dated the 26th June, 1985, in regards to the Degrees and Diplomas granted by the Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh, the following may be added at the end of Item 5—Ph.D.—under “(a) Medical degrees and diplomas) after the words “Orthopaedic Surgery” viz.—“Ophthalmology” and “Oto-Rhino-Laryngology.”

[No. V-17012/1/85-ME(PG)]

KUM. SUMA SUBBANNA, Dy. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 19 सितंबर, 1985

का.आ. 4723.—केन्द्रीय सरकार, परवारी स्थान (अप्राधि कृत अधिनियमों की वेदखली) अधिनियम 1971 (1971 का 40) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 3558 तारीख 23 नवंबर 1978 को उन बातों के विषय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोभ किया गया है श्री आर. राजागोपाल, उपनिदेशक, राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली, को जो सरकार के एक राजपत्रित अधिकारी हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है, जो राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, 22 शामनाथ मार्ग, दिल्ली या उसके द्वारा या उसकी ओर से पट्टे पर किए गए और उक्त संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन के स्थानों की बाबत उक्त अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सम्पदा अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उन पर अधिरोपित शक्तियों का पालन करेगा।

[सं. टी-15020/1/85-पी. एच. (सी.डी.एल.)/पी.एच.]

शोभना सुब्रह्मण्यम, अवर सचिव

## MINISTRY OF HEALTH &amp; FAMILY WELFARE

(Department of Health)

New Delhi, the 19th September, 1985

S.O. 4723.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Premises (Eviction of Unauthorised

Occupants) Act, 1971 (40 of 1971) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) No. S. O. 3558 dated the 23rd November, 1978, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints Shri R. Rajagopal, Deputy Director, National Institute of Communicable Diseases, 22-Sham Nath Marg, Delhi, being a gazetted officer of the Government, as Estate Officer for the purposes of the said Act, who shall exercise the powers conferred, and perform the duties imposed on estate officers by or under the said Act, in respect of the premises belonging to or taken on lease by or on behalf of the National Institute of Communicable Diseases, 22-Sham Nath Marg, Delhi, and under the administrative control of the said Institute.

[No. T. 15020/1/85-PH(CDL)/PH]

KUM. SHOBHANA SUBRAMANIAN, Under Secy.

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

(सिंचाई विभाग)

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 1985

का.आ. 4724.—बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम 1976 (1976 का 63) की धारा-7 की उपधारा (i) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने श्री रमेश चन्द्र, भारतीय लेखा तथा लेखा-परिक्षा सेवा, की बेतवा नदी बोर्ड, झांसी के विश्व सहायकार के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को एक वर्ष की और अवधि अर्थात् 30 जून, 1985 से 29 जून, 1986 तक बढ़ाई है।

[सं. 10(50)/84-परि.तीन]

द्विलोचन सिंह साहनी, अवर सचिव

## MINISTRY OF IRRIGATION &amp; POWER

(Deptt. of Irrigation)

New Delhi, the 6th September, 1985

S.O. 4724.—In exercise of the power conferred by sub-Section (i) of the Section 7 of the Betwa River Board Act, 1976 (63 of 1976), the Central Government hereby extends the period of deputation of Shri Ramesh Chandra, IA&AS as Financial Adviser Betwa River Board, Jhansi for a further period of one year with effect from 30th June, 1985 to 29th June 1986.

[No. 10(50)/84-P. III]

T. S. SAHNI, Under Secy.

## नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1985

का. आ. 4725—इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीमों का और संशोधन करने के लिए स्कीम का निम्नलिखित प्रावप, जिसे केन्द्रीय सरकार, डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाना चाहती है, उक्त उपधारा अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रावप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

उक्त प्रावप की बाबत पूर्वोक्त अवधि के पूर्व किसी व्यक्ति से प्राप्त सिन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार विचार करेगी।

## प्रावप—स्कीम

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) संशोधन स्कीम, 1985 है।

(2) यह राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. इससे उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीमों को उस रीति से संशोधित किया जाएगा जैसी उसके स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट है।

## अनुसूची

क्र.सं०	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1	2	3
1. मुम्बई डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1956	(i) खंड 7 के उपखंड (1) में,— (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ii) खंड 8 में, उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा; (iii) खंड 15 में, उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हें मुम्बई पत्तन न्यास द्वारा जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है। अनुज्ञप्ति के बालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।" (iv) खंड 44 के उपखंड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में, "खोर्ड" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, "अध्यक्ष" शब्द रखा जाएगा। (v) खंड 48 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।	
2. मद्रास डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1956	(i) खंड 7 के उपखंड (1) में, (क) मद (ग) में, "रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ख) मद (घ) में, "समायोजन करने" शब्दों का लोप किया जाएगा; (ii) खंड 8 में, उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा; (iii) खंड 15 में, उपखंड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :— " (ग) ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हें मद्रास पत्तन न्यास द्वारा जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिए अनु-	

1	2	3
		<p>क्षति दी गई है, अनुश्रुति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।”</p> <p>(iv) खंड 45 के उपखंड (1) की मद (ii) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा ;</p> <p>(v) खंड 48 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।</p>
3.	कोचीन डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1959	<p>(i) खंड 7 के उपखंड (1) में,—</p> <p>(क) मद (ग) में, “रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और” शब्दों का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(ख) मद (घ) में, “समायोजन करने” शब्दों का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(ii) खंड 8 में, उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(iii) खंड 15 में, उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“(ग) ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हें कोचीन पत्तन न्यास द्वारा जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिये अनुश्रुति दी गई है, अनुश्रुति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।”</p> <p>(iv) खंड 45 के उपखंड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा ;</p> <p>(v) खंड 49 में उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।</p>
4.	विशाखापटनम डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम 1959	<p>(i) खंड 7 के उपखंड (1) में,</p> <p>(क) मद (ग) में, “रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और” शब्दों का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(ख) मद (घ) में, “समायोजन करने” शब्दों का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(ii) खंड 8 में, उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(iii) खंड 14 में, उपखंड (1) में मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—</p> <p>“(ग) ऐसे व्यक्तियों को भी, विशाखापटनम पत्तन न्यास द्वारा जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिए अनुश्रुति दी गई है, अनुश्रुति के चालू रहने के दौरान स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।”</p> <p>(iv) खंड 44 के उपखंड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में, “बोर्ड” शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहाँ वे आते हैं, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा ;</p> <p>(v) खंड 48 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।</p>
5.	मारमुगाओ डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1965	<p>(i) खंड 7 के उपखंड (1) में,</p> <p>(क) मद (ग) में “रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और” शब्दों का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(ख) मद (घ) में, “समायोजन करने” शब्दों का लोप किया जाएगा ;</p> <p>(ii) खंड 8 में, उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा ;</p>

1

2

3

- (iii) खंड 16 में, उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्न—  
लिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—  
“(ग) ऐसे व्यक्तियों को भी जिन्हें मारमुगाओं पत्तन न्यास  
द्वारा जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिए  
अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान  
स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।”
- (iv) खंड 46 के उपखंड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में,  
“बोर्ड” शब्द के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं,  
“अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा;
- (v) खंड 50 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।

6. कांडला डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1969 (i) खंड 7 के उपखंड (1) में,  
(क) मद (ग) में, “रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और” शब्दों का  
लोप किया जाएगा;  
(ख) मद (घ) में, “समायोजन करने” शब्दों का लोप  
किया जाएगा;
- (ii) खंड 8 में, उपखंड (घ) का लोप किया जाएगा;
- (iii) खंड 16 में, उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्न—  
लिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(ग) ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हें कांडला पत्तन न्यास द्वारा  
जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिए अनुज्ञप्ति  
दी गई है, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान स्कीम के  
अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।”
- (iv) खंड 46 के उपखंड (1) की मद (ii) में उपमद (ख) में,  
“बोर्ड” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं,  
“अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा;
- (v) खंड 50 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।

7. कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) स्कीम, 1970 (i) खंड 7 के उपखंड (1) में,  
(क) मद (घ) में, “रजिस्ट्रीकृत कर्मचारियों और” शब्दों का  
लोप किया जाएगा;
- (ख) मद (ङ) में, “समायोजन करने” शब्दों का लोप किया  
जाएगा;
- (ii) खंड 8 में, उपखंड (ख) का लोप किया जायेगा;
- (iii) खंड 17 में, उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्न—  
लिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(ग) ऐसे व्यक्तियों को भी, जिन्हें कलकत्ता पत्तन न्यास  
द्वारा जहाजी कुलियों के रूप में कृत्य करने के लिए  
अनुज्ञप्ति दी गई है, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान  
स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया समझा जाएगा।”
- (iv) खंड 48 के उपखंड (1) की मद (ii) में, उपमद (ख) में,  
“बोर्ड” शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे  
आते हैं, “अध्यक्ष” शब्द रखा जाएगा;
- (v) खंड 52 में, उपखंड (2) का लोप किया जाएगा।

## MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 19th September, 1985

S.O. 4725.—The following draft of a Scheme further to amend various Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes specified in the Schedule annexed hereto, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Dock Workers (Regulation of Employment) Act, 1948 (9 of 1948), is hereby published as required by the said sub-section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to said draft before the aforesaid period will be taken into consideration by the Central Government.

## DRAFT SCHEME

1. (1) This Scheme may be called the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Scheme, 1985.

(2) It shall come into force on the date of its final publication in the Official Gazette.

2. The Dock Workers (Regulation of Employment) Schemes mentioned in column 2 of the Schedule annexed hereto are hereby amended in the manner specified in column 3 thereof.

## SCHEDULE

S.No.	Short title	Amendment
(1)	(2)	(3)
1. The Bombay Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956		<p>(i) in clause 7, in sub clause (1), (a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;</p> <p>(iii) in clause 15, in sub-clause (1) for item (c), the following shall be substituted, namely :—</p> <p>"(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Bombay Port Trust shall also be deemed to have been registered under the scheme during the currency of the licence.";</p> <p>(iv) in clause 44, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board", at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted.</p> <p>(v) in clause 48, sub-clause (2) shall be omitted.</p>
2. The Madras Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956		<p>(i) in clause 7, in sub-clause (1),—</p> <p>(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;</p> <p>(b) in item (c), the word "adjusting" shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;</p> <p>(iii) in clause 15, in sub-clause (1) for item(c), the following shall be substituted, namely :—</p> <p>"(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Madras Port Trust shall also be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.";</p> <p>(iv) in clause 45, in sub-clause (1) in item (ii), in sub-item (b) for the word "Board" at both the places where it occurs, the word "Chairman" shall be substituted.</p> <p>(v) in clause 49, sub-clause (2) shall be omitted.</p>
3. The Cochin Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959		<p>(i) in clause 7, in sub-clause (1),—</p> <p>(a) in item (c), the words "registered employers and" shall be omitted;</p> <p>(b) in item (d), the word "adjusting" shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;</p> <p>(iii) in clause 15, in sub-clause (1), for item (c), the following shall be substituted, namely :—</p>

(1)	(2)	(3)
		<p>“(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Cochin Port Trust shall also be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;</p> <p>(iv) in clause 45, in sub-clause (1), in item (ii) in sub-item (b), for the word “Board”, at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted.</p> <p>(v) in clause 49, sub-clause (2) shall be omitted;</p>
4. The Visakhapatnam Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1959.		<p>(i) in clause 7, in sub-clause (1), (a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted;</p> <p>(b) in item (d) the word “adjusting” shall be omitted.</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;</p> <p>(iii) in clause 14, in sub-clause (1) for item (c), the following shall be substituted, namely :—</p> <p>“(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Visakhapatnam Port Trust shall also be deemed to have been registered under the scheme during the currency of the licence.</p> <p>(iv) in clause 44, in sub-clause (1) in item (ii) for sub-item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted.</p> <p>(v) in clause 48, sub-clause (2) shall be omitted.</p>
5. The Mormugao Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1956.		<p>(i) in clause 7, in sub-clause (1).—</p> <p>(a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted.</p> <p>(b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted;</p> <p>(iii) in clause 16, in sub-clause (1), for item (c), the following shall be substituted, namely :—</p> <p>“(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Mormugao Port Trust shall also be deemed to have been registered under the scheme during the currency of the licence.”</p> <p>(iv) in clause 46, in sub-clause (1), in item (ii), in sub item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted.</p> <p>(v) in clause 50, sub clause (2) shall be omitted.</p>
6. The Kandla Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1969		<p>(i) in clause 7, in sub clause (1).—</p> <p>(a) in item (c), the words “registered employers and” shall be omitted;</p> <p>(b) in item (d), the word “adjusting” shall be omitted;</p> <p>(ii) in clause 8, sub-clause (d) shall be omitted.</p> <p>(iii) in clause 16, in sub clause (1), for item (c), the following shall be substituted, namely :—</p> <p>“(c) persons have been licenced to function as stevedores by the Kandla Port Trust shall also be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;</p> <p>(iv) in clause 46, in sub-clause (1), in item (ii), for sub item (b), for the word “Board” at both the places where it occurs, the word “Chairman” shall be substituted;</p> <p>(v) in clause 50, sub clause (2) shall be omitted;</p>
7. The Calcutta Dock Workers (Regulation of Employment) Scheme, 1970		<p>(i) in clause 7, in sub-clause (1).—</p> <p>(a) in item (d), the words “registered employers and” shall be omitted;</p>

- (b) in item (e), the word "adjusting" shall be omitted;
- (ii) in clause 8, sub-clause (b) shall be omitted;
- (iii) in clause 17, in sub-clause (1), for item (c), the following shall be substituted, namely :—  
“(c) persons who have been licenced to function as stevedores by the Calcutta Port Trust shall also be deemed to have been registered under the Scheme during the currency of the licence.”;
- (iv) in clause 48, in sub-clause (1), in item (ii), in sub-item (b), for the word "Board" at both the places where it occurs the word "Chairman" shall be substituted;
- (v) in clause 52, sub-clause (2) shall be omitted.

[F.No. LDO/49/82-L.IV]

V. SANKARALINGAM, Dy. Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 1985

का०आ० 4726.—न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का० आ० 2396, तारीख 10 मई, 1983 का अधिक्रमण करते हुए, केन्द्रीय सरकार, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय, नई दिल्ली में उपमुख्य-श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), श्री एस० के० दास को भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 395(अ) तारीख 28 मई, 1981 के अधीन गठित न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त करता है।

[सं० एस०-32023/11/83-इन्क्यू सी(एम इन्क्यू)]

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 13th September, 1985

S.O. 4726.—In exercise of the powers conferred by rule 6 of the Minimum Wages (Central) Rules, 1950 and in super-session of notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 2396 dated the 10th May, 1983, the Central Government hereby appoints Shri S. K. Das, Deputy Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi, in the Office of the Chief Labour Commissioner (Central), New Delhi to be the Secretary of the Minimum Wages Advisory Board constituted under the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 393 (E) dated the 28th May, 1981.

[No. S-32023/11/83-W.C. (M.W.)]

का०आ० 4727.—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3(ii) तारीख 6 अगस्त, 1984 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 567(अ)

तारीख 21 मई, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में श्री एच०जी० भावे के स्थान पर श्री ए०के० दास का नाम अंतःस्थापित किया जाये।

[सं० एस०-32019/4/83-इन्क्यू सी (एम इन्क्यू)]

पी० राघवन, उप सचिव

S.O. 4727.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour No. S.O. 567(E) dated the 21st May, 1984 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 6th August, 1948, namely:—

In the said notification the name of Shri S. K. Das, shall be substituted in place of Shri H. G. Bhawe.

[No. S-32019/4/83-W.C. (M.W.)]

P. RAGHAVAN, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 19 सितम्बर, 1985

का०आ० 4728.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-9-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 19th September, 1985

S.O. 4728.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1985.



## ANNEXURE

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL, KANPUR

I. D. NO. 145/81

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri M.L. Tripathi, C/o. The Assistant Secretary, UP Bank Employees Union, Central Office, 36/1, Kailash Mandir, Kanpur. Workman.

AND

The Chief Manager, Central Bank of India, Karanchikhana, Kanpur. Management.

## APPEARANCES:

Shri S. Trivedi representative—for the management.

Shri V. N. Sekhari representative—for the workman.

## AWARD

The Central Government, Ministry of Labour, vide its order dated 30th October, 1981 (L-12012/297/80-D.IIA), has referred the following dispute for adjudication:

"Whether the action of the management in relation to their Ashok Nagar, Branch, Kanpur, in retiring from services Shri M.L. Tripathi, Daftry with effect from 26-8-80 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?"

The case of the workman is that he entered in the bank's service as sub staff in the year 1946 and was promoted in 1973. That his date of birth as per school leaving certificate is 22-10-22; that he should have retired on 22-10-82 in view of para 18.1 of the Bipartite Settlement on completion of 60 years age but he retired on 26-8-80 which is unjust and reasonable and illegal, hence the premature retirement of the workman be set aside and he be deemed in service till 22-10-82 with full back wages.

The management in their written statement have asserted that the workman joined on 26-8-47 and not in the year 1946 as alleged and he was promoted as daftri from 14-4-73 in the same cadre and get scale as peon. It is contended that beside other contention that he joined service on 26-8-47 he informed the bank that his date of birth was Ashwin Samwat 1976 which according to the Gragerin calendar terms to be 26-8-22 and accordingly this date was recorded as workman's date of birth in bank record. The workman later on had informed the bank that his date of birth was 13-10-22 and on observing this discrepancy the workman was asked by the management to submit satisfactory evidence about his age and date of birth. In consequence, the workman produced the horoscope according to which workman's date of birth was 22-10-22. The third date of birth was brought in picture and this was different from the other two dates of births i.e. 26-8-22 entered in the bank's record and 13-1-22. These dates were at variance and the workman had not produced any satisfactory evidence in support of his contention. He was issued a notice dated 12-8-80 retiring him as treating him as retired from service from 26th August, 1980, on the basis of the date of birth already recorded in the bank's record. The workman thereafter produced a School Leaving Certificate on 23-8-80, wherein his date of birth as 22-10-22 mentioned. Considering the fact that he had not produced any certificate at the time of entering in the bank's service and if he had received any education in any institution school certificate was not given. Secondly the school leaving certificate was not given any attention. On 2nd October, 80, the management bank issued a circular no. BID-14-70-68 that in no circumstances application for altering the date of birth will be entertained and as the date of birth record in the bank at the time of their appointment will stand. Despite the bank's circular, the bank was prepared to give the workman a chance to support his contention regarding the date of birth but the workman did not produce any document and also did not avail of the opportunity offered to him on 26-8-80.

In rejoinder workman admitted that he entered in service in August 1947 and not in 1946 and regretted for the error. He further submitted that Ashwin Samwat 1976 as his date of birth and has expressed his surprise as to how this date

of birth was appeared in his record. Here he states that alongwith the application for appointment in the year 1947 he had given a school leaving certificate as 22-1-22 and he was filing a photostate copy of the same which is annexure B. It is further averred that letter was duly received and it shows the correct date of birth as 22-10-22. It has been ment was in possession of the workman this should have argued by the counsel for the management that if this document was in possession of the workman this should have been filed long ago and not during the pendency of this case. The first opportunity to file was soon after October, 1970. Further before his retirement a notice was given to him that the workman should have filed this and not at this stage. This document appears to be a fake document and prepared for the purposes of this case. The workman has again averred that in the month of January 68 he was asked to satisfy his date of birth. The workman's reply is dated 11-1-68 in which he reiterated his date of birth as 22-10-22, and further stated that a copy of school leaving certificate was attached to his application. A photo of the same letter is appended and marked as annexure 'C'. This letter too was delivered against receipt. Again on 26-12-76, he moved an application on the management bank alleging about his two earlier applications. This letter was too received by the bank and the photo copy of the same is annexure D. The workman was given only seven days time to substantiate his stand that his date of birth was 22-10-22 vide letter dated, 1-7-80.

As observed earlier the workman has filed documents alongwith his rejoinder as annexures and annexure B is the photostat copy of the letter dated 11-7-47. In this application it is written that he wants appointment as peon in the emangement bank and that he has read 8th class and that he was enclosing school leaving certificate and the second application is dated 11-1-61 in which he has mentioned about letter of the branch manager asking him to produce certificate of birth within a week in which he mentioned that he had appended school leaving certificate alongwith application for service. In this he mentioned that his date of birth was 22-10-22. Ashwin Month and Day Sunday. He further alleged that in that school leaving certificate his date of birth is of Vikrami Samwat 1979. The last copy of of the application filed by workman is dated 26-12-79. In this letter addressed to the General Manager he intimated that after obtaining horoscope from his mother he learnt that his date of birth was 22-10-22. The day of birth was Sunday and the month was Ashwin Kwar. He further stated that date mentioned in his form may be ignored as they may not be correct and the date mentioned in this letter is correct.

The management has filed the photocopy of the service record ext. M-2 which shows that his date of birth is Ashwin Samwat 1976, and the date of admission in the bank as 26-8-47. The management has filed annexure M-2 circular dated 2nd October, 1970, whereby the members of the staff were intimated that in no circumstances application for altering their date of birth will be entertained and the date of birth recorded in their service record at the time of their appointment on the basis of document produced by them will stand. If really the workman was literate upto 4th Class and has submitted school leaving certificate alongwith application, there was no reason for writing his qualification as nil. Further the management would not have written his date of birth as Ashwin Samwat 1976 of its own accord. Thus this document was prepared soon after the admission of the workman in the management bank on the basis of record supplied at that time.

On behalf of the management Shri P.K. De an officer of the personnel department of the management bank looking after the staff matters appeared in the witness box and on the basis of record averred the case of the management and proved the documents. He has averred therein that Mr. Tripathi produced school leaving certificate which is dated 22-10-22 on 23-8-80 only after receiving the notice dated 12-8-80 which was not accepted. In cross-examination he stated looking original of annexure B stated that the same does not bear the seal of the bank. He further stated that who founded equivalent Ashwin Samawat 1976 as 26-8-80. He further stated that after the circular of 1971 the workman did not file objection and produce school certificate only after receiving the notice of retirement.

On the other hand the workman has reiterated in his rejoinder as well as in the cross-examination that the bank never asked him to give proof of his date of birth. He further stated that after retirement he came to know that in bank's record his date of birth was wrongly recorded. He also deposed that in this case he has filed a school certificate for age whereas matter of fact no such record has been filed. He stated in the end that it was wrong to say that at the time of retirement he gave wrong date of birth so that he may remain in the service of the bank for longer period.

The workman has never filed the school leaving or the horoscope to show authenticity of the two documents. If they really existed further he should have proved the fact from the record of the Nigoha Primary School from original document and also by producing the person who prepared the horoscope or horoscope itself. None of them has been done. Obviously there is no person to disbelieve the entire in the service record of the workman that the date of birth was Ashwin Samwat 1976 and the record was prepared soon after his entry in the service and long before the dispute should be raised immediately earlier in 1961 as stated by the workman. The workman has tried to reconcile the entry made in the service record and the school leaving certificate and horoscope. Firstly in the earlier letter he had stated that it was not Vikarni Samwat 76 but Vikarni Samwat 71. second time stated that it was the date month Ashwin Samwat 1976, but the day of birth was Sunday. Reconciling of these three samwat dates of birth and Ashwin Mah he gave out his date of birth as 22-10-22 and even looking to the Panchang of 1979 month of Ashwin the date 22 does not fall in the month of October and the entire month of Ashwin commencing from 7th September and concludes on 5th October and date 22 falling therein is not Sunday but Friday.

In Samwat 1976 also the entire month commences from 11th September and concludes on 9th October, and date 22nd of September, falls on Monday. Thus in any view of matter this month of Ashwin does not fall in October and in any way date of birth given by the workman as 22-10-22 does not reconcile.

As observed earlier Samwat 1976 and month Ashwin commenced from 11th September and concluded on 9th October. Even taking the last date i.e. 9th Samwat 1976 Ashwin month the workman should have been retired on 9-8-80 and not on 26th October, 80. The month of October does not come in Ashwin 1976 rather it is all September and October. Taking the last date which would be advantageous to the workman I hold that he should have been retired on 9th October, 80 and not on 26-8-80, taking the month of birth mentioned in the service record.

I accordingly hold that the retiring Shri M.L. Tripathi, from 26-8-80 was not justified and he should have been retired on 9-10-80. The result is that he will be entitled to get difference of pay and all benefits till 9-10-80 taking on date as date of birth of his retirement.

I, therefore, give my award accordingly.

Let Six copies of this award be sent to the Government for publication.

Dt. 2.9.85.

R.B. SRIVASTAVA, Presiding Officer  
[No. I-12012/297/80-D. II (A)]

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 1985

का. अ. 4729.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वय में केन्द्रीय सरकार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9-9-85 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd September, 1985

S.O.4729.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Central Bank of India and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1985.

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI R.B. SRIVASTAVA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,

KANPUR

I.D. No. 67 of 1980

Reference No. L-12011/119/78-D.II-A, dated 15th July, 80

In the matter of dispute

BETWEEN

Shri Tej Pal Singh and others,

C/o. Shri Tara Chand Gupta, Joint Secretary, All India  
Central Bank Staff Federation, 91, Sarai Nazar Ali,  
Ghaziabad.

AND

The Divisional Manager, Central Bank of India, Delhi  
Road, Meerut.

#### APPEARANCES:

Shri S. Trivedi, representative for the Management &  
Shri Tara Chand Gupta representative for the Workmen.

#### AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its Notification No. L-12011/119/78-D.II-A dt. 15th July, 1980, has referred the following for adjudication.

"Whether the action of the management of Central Bank of India in relation to its Divisional Office at Meerut in not providing employment to Shri Tej Pal Singh, N. C. Jain, Anil Kumar, Sita Ram and Som Prakash peons, on and from 7-12-75, 21-11-75, 25-3-76, 21-11-75 and 22-2-76 respectively is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled?"

2. The case of the workmen as sponsored by the union is that the management bank is public sector undertaking and comes under the definition of state within the meaning of article 12 of the Indian Constitution. In June 1971, the bank made an advertisement in newspapers inviting applications for recruitment of the sub-staff cadre for its office in Meerut Division. All the five concerned workmen applied for recruitment, and they appeared in written test and interview. The bank finally selected candidates on the basis of the said test and interview and also a list of successful candidates, a copy of which is annexure W-2, filed with the claim statement. The said list contained a separate names of six candidates under separate category, as sons and daughters of the staff members. All the five workmen were initially appointed as temporary peons at different offices of the bank management from different dates and were given temporary employment at various branches under divisional office at Meerut. Subsequently all the six sons of the staff (whose names are in the list as separate category), of separate category and 16 out of 3 general category candidates were given appointment with six months probation but the remaining candidates of the general category including 5 workmen concerned were continued on temporary basis till 1975-76 whereafter no further employment was given to them from the dates mentioned against their names in the reference order. The union raised

industrial dispute which ended in failure but the Government declined to refer the dispute for adjudication on the ground that the management had issued orders for the appointment of the candidates directly according to merit, copy of which is annexure W-7 of the claim statement. After the said the management stopped giving workmen further employment after the date mentioned in the reference order and aggrieved by the such action they made further representation on which the management informed that the Head Office has decided to absorb only those candidates who had worked for 240 days of work in 12 calendar months and that the remaining list (waiting) had been cancelled. The management took five persons for permanent appointment giving them six months probation on the ground that they had completed 290 days in one calendar year. They were given permanent appointment on 14-1-78 and were confirmed on 14-7-78. It may be mentioned here that the name of Shri Anil Kumar workman appeared in the merit list Annexure W-2 filed alongwith claim statement is in between those five workers and had services of Shri Anil Kumar not terminated from 25th March, 76 he must have completed 240 days in one calendar year and became eligible for permanent appointment, as the above said five persons. The aggrieved workmen made representation demanding permanent absorption. At this stage All India Central Bank Staff Federation took up the case of these workmen and raised industrial dispute before ALC (Central), Delhi. The said conciliation proceedings ended in failure on the basis of which the present reference has been made by the Government. Meanwhile the management absorbed from the approved list one Shri N. P. Srivastava, in permanent service w.e.f. 20-7-78 on the ground that he too had completed 240 days in one calendar month. The management absorbed four persons permanently at Ghaziabad branch in 1972, who had not passed any recruitment test though the management had taken plea before the ALC (Central), that the five persons can not be absorbed for non-availability of the vacancies. The management continued recruitment of subordinate staff by holding fresh test in 1972 and transferring the sub staff from one branch to other branches in Meerut Division and those who qualified the test were called for interview and subsequently appointed in the bank ignoring the preferential right of the workmen and the union objected this action of the management by raising objection per annexure W-17 filed with the statement of claim.

3. The bank management in its written statement averred that in 1974 the recruitment test was held for general category candidates and for filling up the backlog of the Schedule Castes candidates as penal prepared in 1971 stood cancellation. The management referred the case law laid down in H. L. Dua versus MSD 1971 2(i) LLJ page 414 Delhi according to which empanelment did not create any right for appointment. They further averred that it was in pursuance of the management recruitment policy circular no. 4 of 1968. Since all the bank employees were recruited on the concession given in the circular though this relaxation was abolished in 1976.

4. It cannot be denied that mere empanelment will not create any right on the person empanelment for getting permanent employment. Further it was within the right of the management to cancel the list for reasons given. The right of the five workmen for being considered in preference of those who were recruited despite their positions being below or that the recruitment of any of them was against law. On this point my attention was drawn to circular no 4 of 1968, annexure 2 whereby sons and daughters of the bank employees were given preference in the matter of employment and were to be selected even if they acquired less numbers of marks than the candidates of general category. Admittedly this practice has been given up from the year 1976. It was after this circular no. 4 which came in bank on 6-5-68, when the bank management was nationalised on 19-7-69, and on having come under control of Government of India it came within the definition of state of article 12 of the Indian Constitution. Article 16 of the said constitution gives right to equality in the matter of public employment. Thus in continuance of the provision of circular no. 4 of 1968 of the management bank after nationalisation of banks or giving preferential treatment to the sons and daughters of the bank employees after the said date was illegal. Admittedly five members of the sons of staff mentioned in annexure W-16 of the W.S. were given employment

after 1978 in preference to the persons who had qualified and whose name appeared in the merit list was illegal and no other person from the merit list should have been chosen. Shri Nirankar Prasad had already been given permanent appointment thus out of the approved list annexure W-16 person appearing at serial no. 23 would be entitled to permanent appointment in own right.

5. Further coming to the point that all those who had put in 240 days of service in one calendar year were given permanent appointment on the basis of Scheduled Caste is not the correct and proper appreciation of law. The law is laid down in the case State Bank of India Vs. M. Sunder Money 1976, 1 LLJ page 478 lays down is that all those temporary workmen having completed 240 days in one span of year comprising of 12 calendar months could not be terminated without paying them retrenchment compensation and notice pay and in case of non-compliance of section 25F of the ID Act they will be deemed to be in continuing in service and as the necessary corollary the management will have to pay them for the period they were out of the service, instead of understanding the law properly as laid down by see itself in subsequent paras he will not be allowed to claim any advantage in the matter of seniority or other priority interse among temporary employees on the ground that his retrenchment is being declared invalid by this court. The management instead of appreciating the law properly that the temporary employees could not be terminated after completion of 240 days in one calendar year by paying them retrenchment compensation, notice or notice pay, they started giving them permanent appointment which again was illegal in preference to those who had appeared in test and interview and came out successful and were there on the successful list and would have been given permanent appointment. Had persons below them and in the garb that they had completed 240 days were given appointment under the mistaken interpretation of law by management. It was clearly laid down in the case law of Shri S. K. Verma and others Vs. C.G.I.T. and others 1980 lab IC 1992, wherein it was held:

The labour court appears to have thought that the award of the relief of reinstatement with full back wages would put these workmen on a par with those who had qualified for permanent absorption by passing the prescribed test and that would create dis-satisfaction amongst the latter. First, they can never be on par since reinstatement would not qualify them for permanent absorption. They would continue to be temporary liable to be retrenched.

6. Permanent appointment of Shri Nirankar Prasad Srivastav be illegal, persons above him namely Shri Anil Nagin Chand, and Sitaram were entitled to be considered first and as such would be entitled to be given appointment first in preference to him. The management should not have considered appointment of four persons in 1972 namely Shri S. C. Singhal, Ramsingh, Achaya Lal and Gulab Singh and giving them appointment in preference to the persons who had passed the test and were approved for appointment of the sub staff vide ann. W-16 of the written statement. The appointment of those four persons in preference to approved list just after a year or so and also it was exhausted, or it was cancelled was illegal. Had they not been taken and person from the approved list appointed all the workmen would have got permanent appointment.

7. The management has raised the objection that the applicants are not workmen. Under the definition of workman those persons are also workmen for the purpose of proceedings under this Act in relation to an industrial dispute who have been dismissed, discharged or retrenched or whose dismissal, discharge is lead to industrial dispute. They have also taken the plea that the reference is bad in law. No cogent reasons have been given as to why the reference is bad. The Central Government in its wisdom did not refer the dispute on the first instance as it considered that the management have issued offers of appointment to the candidates as and when vacancies arose directly according to merit but later on when the matter was taken up by the federation the Government referred the dispute for adjudication. Most of the appointment were made at Ghaziabad, six persons of the category of sons of the staff and junior persons who

had completed 240 days of service in one span of year after termination workman in 1975 or 76. Letter ext. W-8 of the management filed alongwith claim statement show that Shri Dinesh Kumar, Srikrishna Sharma, Dinesh Mohan Sharma V. P. Raju and Khem Chandra were given permanent appointment on the basis of having completed 240 days in 12 calendar months and list was treated as cancelled as it has become more than three years old. This letter was given to the workman Shri Nagin Chandra Jain by the management on 5-4-78. Even after that one N. P. Srivastava was given permanent appointment which too completed 240 days of work in one calendar month.

8. Shri Anil Kumar appeared in the witness box and has deposed that after recruitment 1972 to 1976 he worked in the management bank off on but in none of these years he completed 240 days. According to him that all those who completed 240 days were given permanent appointment in 1978. He has deposed that in the recruitment test of 1974 he did not appear as his appointment list was going on and persons being appointed from that list. In the end he admitted that he working at a shop and getting Rs. 350 per month.

9. Thus the management should have considered giving appointment to the five candidates who were in the approved list or allowed them to continue before terminating their services till the year 1975-76 as alleged.

In Geeth Versus Central Bank of India, Industrial and Labour Cases 71 wherein it was held;

From the final list of candidates selected the names of those candidates who have been approved but could not be given any appointment for want of vacancy, will be kept on a waiting list. Such a list should be prepared for each category of staff and any vacancy arising in these categories during the year should first be offered to such candidates whose names appeared in the first waiting list in the order of merit. Temporary staff if required at any time should also be strictly drawn from this list in other words, no one who has not qualified in the written test and interview should be appointed even as temporary member of staff.

10. In employing persons after termination of the five workmen in 1975-76, the giving appointment of five persons of annexure W-8 and Shri N. P. Srivastava in 1978 is violative of section 25 H of the I D Act as they should have been given appointment first and others later.

11. Thus in view of the discussion made above, I hold that the action of the management of Central Bank of India in relation to its Divisional Office at Meerut in not giving employment to S/Shri Tej Pal Singh, N. C. Jain Anil Kumar Sita Ram and Som Prakash, peons on and from 7-12-75, 21-11-75, 25-3-76, 21-11-75 and 22-2-76, respectively is not justified. The result is that they are entitled to be reinstated in service with full back wages and continuity of service and be given permanent appointments from the date on which their entitlement accrues as per their position in their seniority list.

12. Shri Anil Kumar being gainfully employed and getting Rs. 350 per month shall get balance of pay after adjusting Rs. 350 per month.

13. In the circumstances of the case, the workman shall get Rs. 300/- as cost.

14. I, therefore, give my award accordingly.

15. Let six copies of this award be sent to the government for publication.

Date 2-9-85

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer

[No. L-12011/119/78-D.II (A)(Pt.)]

N. K. VERMA, Desk Officer

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 1985

आ. आ. 4730:—केन्द्रीय सरकार कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र भाग 2, के खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 5 अक्टूबर 1968 में प्रकाशित श्रम, मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3483 तारीख 24 सितंबर, 1968 को जिसके द्वारा अधिनियम के उपबंध मैसर्स पी. टी. सम्पत्तकुमारन एण्ड कंपनी चार्टर्ड ए. जे. उन्टेन्ट्स, 193, माउन्ट रोड, मद्रास-2 को लागू किए गए थे तुरन्त प्रभावी रूप में निर्रिक्त करती है।

[एस. 70013(1)/84 पी एफ. II (एसएस II)]

ए. के. भट्टराई, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd September, 1985

S.O. 4730.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the Section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government in the Ministry of Labour hereby rescinds with immediate effect notification No. S.O. 3482 dated 24th September, 1968 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 5th October, 1968 applying the provisions of the Act to M/s. P. T. Sampathkumaran and company chartered Accountants, 193, Mount Road, Madras-2.

[S-70013(1)/84-PF II(SS-II)]

A. K. BHATTARAI, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 सितंबर, 1985

आ. आ. 4731:—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूरदर्शन केन्द्र जयपुर के प्रबंधन से संबंधित निराजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्विष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10 सितंबर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 23rd September, 1985

S.O. 4731.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the following award of the Central Industrial Tribunal, Rajasthan Jaipur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Doordarshan Kendra, Jaipur and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN.  
JAIPUR

Case No. C.I.T. 17/81

REFERENCE:

Under Secretary, Government of India, Ministry of Labour, New Delhi, Order No. L-42012(35)/ 81-D.II(B) dated 15-12-81.

In the matter of an Industrial Dispute.

BETWEEN

Late Shri Ganga Shanker Vyas through his legal representative Smt. Manglesh Kumari Vyas.

Vs.

Station Engineer, Doordarshan Kendra, Jaipur.

## RESENT:

Smt. Mohini Kapur, R.H.J.S.

For the Applicant—Shri R. S. Mehta.

For the Non-Applicant—Shri S. L. Sabhnani

Date of Award—26-3-85.

## AWARD

The Central Government has referred the following dispute for adjudication.

"Whether the action of the Station Engineer, Doordarshan Kendra, Jaipur in terminating the service of Shri G. S. Vyas, General Assistant on casual basis with effect from the 17th February, 1979 without following the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 is justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. The workman Shri G. S. Vyas, the validity of whose termination of service is to be adjudicated, expired during the pendency of this dispute and his widow Smt. Manglesh Kumari and minor children were brought on record as representatives by order dated 25-11-83. The question of reinstatement does not arise now and the only relief which can be granted, if found due, will be compensation.

3. The deceased Shri G. S. Vyas was appointed in Doordarshan Kendra, Jaipur as a General Assistant on 14-2-77 on daily wages and contract basis. He worked like this upto 11-7-77 with some breaks and from 15-7-77 he was taken on muster roll basis. He was given a monthly salary and was asked to discharge duties on all days of month but he was not given benefits of holidays and Sundays. When he raised his voice against this practice he was immediately removed from service. A pay scale of Rs. 260 to Rs. 400 for General Assistant existed but he was not given this pay scale. He used to maintain different types of registers such as contract register, attendance register, car log register, programme tapes receipt and despatch register, telegaram receipt and despatch register, stationary stock register, receipt and despatch register etc, besides doing typing and other work. He worked for more than two years in all without any clerk under him. He was made to work from 9 a.m. to 7 p.m. and sometimes even up to 10 p.m. He was assured from time to time that complete dues would be paid to him but instead of this he was removed from service without following the provisions of section 25 F of the Industrial Disputes Act even though he had completed more than 240 days in service.

4. The opposite party has admitted that Shri G. S. Vyas was first engaged on casual contract basis for 14 days, and then on daily wages but this engagement was purely casual in nature. He was engaged on daily wages as and when there was work and whenever his services were required, he was called for the job and the break in service were not deliberate. It is denied that he was taken as a regular employee on muster roll. It is pleaded that as he was a purely casual employee on daily wages, the provisions of section 25F are not applicable. It is pleaded that Doordarshan Kendra is not an industry as it does not do any business or trade and it is not an undertaking or manufacturing concern.

5. The action of the opposite party in dispensing with the services of Shri G.S. Vyas is sought to be justified on the ground that he was appointed on casual basis. The only oral evidence in this case is of station Engineer, Jaipur Doordarshan Kendra, Shri Sharda Prasad Srivastava who has deposed that Shri Vyas was engaged on daily wages by different orders which are Ex. M1 to Ex. M6 when a regular person selected by the Service Selection Commission was posted that Shri Vyas was no longer kept in service. He has admitted that Shri Vyas had worked for more than 240 days in a year and when he was removed from service in Feb., 1979 he was not given any notice or compensation. When Shri Vyas worked for more than two years and for more than 24/ days in a year he was entitled to notice or pay in lieu of notice and compensation as required under section 25 F of the Industrial Disputes Act. This provision is applicable to casual workman also and merely because Shri Vyas was not a regularly selected permanent employee, it does not mean that he is not covered by the definition of 'the workman under section 2 (s) of the Industrial Disputes Act. The termination of his service without following the necessary provisions of law is illegal.

6. The only question which is of relevance in this connection is whether the opposite party, Doordarshan Kendra, Jaipur is an industry under the provisions of the Industrial Dispute Act. The witness examined by the opposite party has stated that at Jaipur Doordarshan Kendra they are not transacting any business or making income as they only relay programmes from Delhi. On this basis, it is contended that it is not an industry to which the provisions of the Industrial Disputes Act are applicable. Relying on A.I.R. 1978 S.C. 548, Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs A. Rajappa and others, it is contended that for an industry there has to be a systematic activity organised by the cooperation between the employer and employee for the production and/or distribution of goods and service calculated to satisfy human wants and wishes. It was also observed that absence of profit motive or gainful objectives is irrelevant, be the venture in the public, joint, private or other sector. The decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer employee relations. Reference is made to para 18 and 19 of this judgement which read as under:—

18. I would also like to make a few observations about the so-called 'sovereign' functions which have been placed outside the field of industry. I do not feel happy about the use of the term 'sovereign' here. I think that the term 'sovereign' should be reserved technically and more correctly, for the sphere of ultimate decisions. Sovereignty operates on a sovereign plane of its own as I suggested in Keshavananda Bharati's case, A.I.R. 1973 S.C. 1461, supported by a quotation from Ernest Barker's 'Social and Political Theory'. Again, the term 'Regal', from which the term 'sovereign' functions appears to be derived, seems to be misfit in a Republic where the citizen shares the political sovereignty in which he has even a legal share, however small, in as much as he exercises the right to vote. What is meant by the use of the term 'sovereign' in relation to the activities of the State, is more accurately brought out by using the term governmental functions although there are difficulties here also in as much as the Government has entered largely now fields of industry. Therefore, only those services which are governed by separate rules and constitutional provisions such as Articles 310 and 311 should, strictly speaking, be excluded from the sphere of industry by necessary implication.

19. I am impressed by the argument that certain public utility services which are carried out by government agencies or corporations are treated by the Act itself as within the sphere of industry. It expressly rules under other enactments govern the relationship between the State as an employer it may be contended, on the strength of such provisions, that a particular set of employees are outside the scope of the Industrial Disputes Act for that reason. The special excludes the applicability of the general. We cannot forget that we have to determine the meaning of the term 'industry' in the context of and for the purposes of matters provided for in the Industrial Disputes Act only."

Referring to these decisions it is contended that All India Radio has not been held to be an industry therefore Doordarshan Kendra cannot be an industry under the Industrial Disputes Act.

7. The witness who came for the opposite party has laid stress in the evidence on the fact that the Jaipur Doordarshan Kendra is not having any income and is merely relaying programmes from Delhi. In this connection it may be stated that income or profit motive is not essential for an establishment to be an industry. It is the nature of the activity carried on by the employer and employee which is of relevance. The systematized activity in this case is producing programmes and telecasting for the entertainment and satisfaction of the public which can also be said to be distributing and sharing knowledge and making the people better informed. This amounts to rendering service to the public through the cooperation of employer and employee. All this activity suggests that Doordarshan is an industry. It may also be mentioned that with the commercialisation of the television programmes it can no longer be said that Doordarshan's aim is merely philanthropic. The objection of the opposite party has no force.

8. The question to be decided now is what compensation should be granted to the widow of Shri G.S. Vyas. Shri Vyas was illegally removed from service in Feb., 1979 and he died on 29-12-82. Had his case been decided earlier he would have been reinstated in service, but that question is no longer relevant now and only a lump-sum compensation can be awarded on account of the illegal termination of service. He was engaged on Rs. 14/- per day and the monthly income may be said to Rs. 360/-. He would have normally earned about Rs. 4000/- per year and at this rate he would have earned a little over Rs. 15000/- till Dec., 1982. However, his service was not regular and it could have been validity terminated at any time. Moreover as compensation is being paid in lump-sum, I would consider it proper that a sum of Rs. 10000/- by way of compensation should be given to the widow and children of Shri G.S. Vyas.

9. An award is passed that the termination of service of Shri G.S. Vyas is illegal. His widow and minor children are entitled to a compensation of Rs. 10000/-.

10. The award is to be sent to the Central Government for publication.

SMT. MOHINI KAPUR, Judge  
[No. L-42012 ((35)/81-D. II (B))]

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

का. आ. 4732 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार मैसर्स बिसरा स्टोन लाइम स्टोन माइन्स कम्पनी, लिमिटेड, डाकघर बिरमित्रा पुर, जिला सुन्दरगढ़ के प्रबंध-तंत्र से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, भुवनेश्वर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11, सितम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 25th September, 1985

S.O. 4732.—In pursuance of section 17 of the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Bhubaneswar (Orissa) as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Bisra Stone Lime Stone Mine Co. Ltd., Post Office Birmatrapur District Sundergarh, (Orissa) and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th September, 1985.

INDUSTRIAL TRIBUNAL, ORISSA, BHUBANESWAR

PRESENT :

Shri K. C. Rath, B.L.,  
Presiding Officer,  
Industrial Tribunal,  
Bhubaneswar.

Industrial dispute Case No. 3 of 1983 (Central)  
Dated Bhubaneswar, the 28th August, 1985.

BETWEEN :

The Management of M/s Bisra Stone  
Lime Stone Mine Co. Ltd.,  
Birmatrapur.

First-party

AND

Their workmen.

Second Party

APPEARANCES :

Shri D. Naik, Advocate—for the first party.

Shri G. Pujari, Advocate—for the second-party.

## AWARD

Dispute referred to by the Central Government for adjudication under Clause (d) of Sub-section (1) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, vide Notification No. L-29012/8/82.D.II(B) dated 1-7-1983 of the Ministry of Labour & Rehabilitation, Department of Labour, reads thus :

"Whether the retirement of Shri Mangaram Deep, Dumper Operator on medical grounds with effect from 31-1-82 by the management of M/s Bisra Stone Co. Ltd., Birmatrapur is justified? If not, to what relief Shri Mangaram Deep is entitled to?"

2. First-party employer is M/s. Bisra Stone Mine Co. Ltd., Birmatrapur, whereas the second-party workman was its Leyland Dumper Operator from 10-4-1962 till 31-1-1982 when he was forced to retire after due notice on medical ground.

3. Second-party workman filed a written-statement stating that even though he was suffering from incurable diseases like diabetes and arthritis but they were controllable. In fact, the diseases were controlled after treatment and he was found fit by the Assistant District Medical Officer, Balangir, on 9-12-1981 and by the then District Medical Officer on 16-4-1982 and yet he was asked to go on retirement without any just cause or excuse and as such, the impugned order retiring him from service is illegal and motivated.

4. First-party employer filed its rejoinder stating that the second-party absented himself frequently from duty on the ground of illness for which his medical examination was held and as per the information of the Medical Officer that he was unfit to hold the post of dumper operator any further, he was forced to retire with effect from 31-1-1982 after notice.

5. The second-party examined himself and first-party examined three witnesses in support of their respective contentions. The witness No. 1 examined for the management is the Medical Officer who exhibited the relevant documents of the hospital and stated that the second-party workman was on sick leave for 86 days in 1978, 57 days in 1978, 161 days in 1980 and 168 days in 1981. He was referred to Ispat General Hospital, Rourkela, for treatment twice. Lastly he was examined by a Medical Board on 21-12-1981 and was found to be unfit to operate the Leyland dumper on account of continued ill-health. The witness No. 2 is the Superintendent (Mechanical) under whom the second-party was working and his evidence discloses that the second-party was remaining absent from duty on the ground on his sickness. The witness No. 3 is the Senior Personnel Manager who exhibited Ext. G which would go to show that the second-party applied for leave for treatment at his own cost and his prayer was allowed. He denied that the second-party produce any document certifying his fitness for the job subsequent thereto. That the second-party applied for leave as per Ext. G is admitted by the second-party himself but his case is that he came round after treatment. The doctor who treated him is not examined. Certificate, if any, granted by the doctor is also not exhibited. No attempt is also made to produce the certificate, if any, of the concerned doctor before the medical board. In view of all these the plea taken by him that he came round after treatment cannot be believed and it must be found, taking into consideration the fact that the second-party workman frequently absented himself from duty on the ground of his sickness from incurable diseases like arthritis and diabetes, that he was rightly declared unfit by the Medical Board for holding the post of Leyland Dumper Operator in the mines area any further, and as such, the impugned order retiring him from service on medical ground under Clause 27(a) of the Standing Orders must be maintained.

6. In the result, the retirement of Shri Mangaram Deep, Dumper Operator on medical grounds with effect from 31-1-1982 by the management of M/s. Bisra Stone Lime Co. Ltd., Birmatrapur, is justified.

7. The Award is passed accordingly.

K. C. RATH, Presiding Officer  
[No. L-29012(3)/82-D.II(B)]

का. आ. 4733 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार अर्थफील्ड प्रोडक्स (बम्बई) प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण जयपुर (राज.) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 11 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4733.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur (Rajasthan), as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Earthfield Products (Bombay) Private Limited, and their workmen, which was received by the Central Government on the 11th September, 1985.

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर।

केस नं. सी. आई. टी. 29/1984

केन्द्रीय सरकार श्रम मंत्रालय अधिसूचना संख्या एल 43011 (4)/83 डी III (बी) दिनांक 23-1-84  
बैनल माइन श्रमिक संघ उदयपुर।

बनाम

मै. अर्थ फील्ड प्रोडक्ट्स प्रा. लि. बम्बई :

संघ की ओर से                      कोई नहीं  
नियोजक की ओर से            श्री नरेन्द्र प्रकाश मटठा  
दिनांक अर्वाड                    6-7-85

अर्वाड

केन्द्र सरकार निम्नलिखित विवाद इस न्यायाधिकरण को वास्ते निपटारा अपनी अधिसूचना संख्या. एल-43011 (4)/83-डी III (बी) दिनांक 23-1-84 के द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10 (1) के अन्तर्गत भेजा है :—

“Whether the action of the Management of M/s. Earthfield Products (Bombay) Private Limited in closing down their Bansal Asbestor mines with effect from the 25th July, 1981 without complying with the provisions of section 25 FFF of the Industrial Disputes Act, 1947 is justified? If not, to what relief are the workmen concerned entitled.”

श्री नरेन्द्र प्रकाश मटठा विपक्षी की ओर से उपस्थित हैं। संघ की ओर से कोई हाजिर नहीं है। आज संघ को स्टेटमेंट आफ क्लेम पेश करना है लेकिन कोई हाजिर नहीं है। संघ को नोटिस तामिन हो चुका है। वाद तामिन संघ की ओर से कोई हाजिर नहीं है, और न ही क्लेम पेश हुआ ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाद में संघ रुचि नहीं लेता है अतः इस विवाद में नो डिस्प्यूट अर्वाड पास किया जाता है। जो केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भेजा जावे।

श्रीमती मोहिनी कपूर, न्यायाधीश

[सं. एल-43011(4)/85-डी III (बी)]

का. आ. 4734 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, जैन मिनेरल, बेआवर के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच अनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, जयपुर (राज.) के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 10 सितम्बर, 1985 को प्राप्त हुआ था।

S.O. 4734.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, Jaipur (Rajasthan), as shown in the Annexure, in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Messrs Jain Minerals, Beawar and their workmen, which was received by the Central Government on the 10th September, 1985.

CENTRAL INDUSTRIAL TRIBUNAL, RAJASTHAN, JAIPUR

Case No. C.I.T. 33/82

REFERENCE :

Desk Officer, Government of India, Ministry of Labour  
Order No. L-29011/8/82-D.III(B), dated 8th October, 1982.

Khan Mazdor Union, T. L. Unit Building, Beawar.

Vs.

Jain Minerals Mine Owners and Minerals Suppliers,  
Ajmer.

In the matter of an Industrial Dispute.

PRESENT :

Smt. Mohini Kapur, R.H.J.S.

For the Applicant :                      Shri J. L. Shah.  
For the Opposite Party :                Shri P. L. Agarwal.  
Date of Award :                            28-5-85.

AWARD

The Central Government has referred the following dispute for adjudication.

“Whether the demand of the workmen employed in the mine at Jawaja and Raipur Panchayat area of M/s. Jain Minerals, Ajmer for payment of profit sharing bonus at the rate of 20 per cent of their wages for the Accounts year 1978-79 and 1979-80 is justified.

Whether the demand of the workman employed in the mines at Jawaja and Raipur Panchayats of M/s Jain Minerals Ajmer for grant of seven days casual leave and twelve days Festival and National holidays with payment is justified.

Whether the demand of the workman employed in the mines at Jawaja and Raipur Panchayat area of M/s. Jain Minerals, Ajmer for issuance of attendance card is justified.

Whether the action of the management of M/s. Jain Minerals Ajmer in terminating the service of the following workmen w.e.f. 1st May, 1981 without



following the procedure as laid down in the Industrial Disputes Act, and without paying their legal dues is justified.

1. Shri Gulab Singh S/o Himat Singh
2. Shri Mal Singh S/o Himmat Singh
3. Shri Khem Singh S/o Durg Singh
4. Shri Keesa Singh S/o Gain Singh
5. Shri Lal Singh S/o Teel Singh
6. Shri Bheru Singh S/o Raju Singh
7. Shri Mal Singh S/o Bheru Singh
8. Smt. Mohini W/o Gulab Singh
9. Smt. Tulsi W/o Mal Singh
10. Smt. Radha W/o Kanghar Singh
11. Smt. Jamku W/o Himmat Singh
12. Smt. Dhuri W/o Gain Singh
13. Smt. Sita W/o Mor Singh
14. Smt. Mogi W/o Bheru Singh
15. Smt. Dakhu W/o Man Singh.
16. Smt. Chandra W/o Man Singh
17. Smt. Pathasi W/o Dudu Singh.
18. Smt. Panni W/o Som Singh

If not, to what relief are the workmen entitled."

2. The Union which raised the dispute, submitted a seven point demand charter to the employer, on which no settlement could be arrived at and the Central Government has referred only four demands for adjudication. Out of these four matters one relates to the termination of service of eighteen workmen. As for other demands of the charter, the first demand is about the bonus at the rate of 20 per cent per at the rate of on the ground that the opposite party, who is having mine business for the last 14-15 years, is earning a huge profits. The accounts maintained by it are said to be incomplete in order to conceal the real income. The second demand is for seven days casual leave and twelve days national and festival holiday with pay in a year. It is alleged that in other mines this facility is provided to the workmen. According to the claim, the holidays allowed under the Mines Act are also not given by the opposite party. Another demand is about the issue of attendance cards. The attendance register is maintained by the employer and the workmen are not allowed to enter their own attendance. If attendance cards are issued then the workman will be aware of leave weekly holidays, etc. as they will be having record of it. As for the dispute of the termination of service of 18 workmen, it is stated that they were in service since 1979 and they were paid according to piece rate. When these workmen demanded their full wages, the employer got annoyed with them and orally terminated the service of these workman. It is alleged that they had worked for more than 240 days in each year, but were not paid compensation or pay in lieu of notice.

3. The opposite party has first of all contested the status of the sponsoring Union. No employee of Jawaja and Rampur Panchayat area is said to be a member of the petitioner Union. Similarly in regard to 18 workmen or employees, whose services are said to have been terminated, it is stated that they were not employees of this establishment. The demand charter submitted by the Union, was suitably replied. It is submitted that there is no dispute with the employees of the opposite party and the Union has quite unnecessarily raised the dispute. The demand for bonus at the rate of 20 per cent is denied on the ground that the establishment handled by the opposite party is on a very small scale which does not have much profits. They are already paying statutory bonus to its employees. All the employees are said to be engaged on daily wages and no C. L. is allowed in similar type of business. It is pleaded that attendance cards are regularly given to the employees.

4. In the documents, submitted by the opposite party, there is the reply to the demand charter and the reply submitted before the Conciliation Officer. Besides attendance register, payment registers have been submitted along with the production register. Two applications signed by the workmen of the establishment have been submitted which are to the effect that they have resigned from the membership of this Union and they do not want any demand to be raised.

However, no one has come forward to prove them. The Union has not led any evidence inspite of several opportunities given to it. Even from the documents produced by the opposite party it cannot be said that the income of the opposite party is in a higher category so as to allow 20 per cent bonus per month.

5. The opposite party is maintaining attendance register and payment register and no one has come to depose that attendance cards are issued. Similarly as for the leave allowed in other mines in this region there is no evidence on behalf of either side. None of the 18 workmen whose services are said to have been terminated without following the procedure has come forward to depose that he had worked with the opposite party for a particular period. In absence of any evidence it is not possible for me to come to the conclusion that any of the demands submitted by the sponsoring union are justified.

6. In the result a no dispute award is passed which is sent to the Central Government for publication in accordance with law.

SMT. MOHINI KAPUR, Judge,

[No. L-29011/8/82-D. III(B)]

HARI SINGH, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

का.आ. 4735:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिारण चंडीगढ़ के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9 सितम्बर 1985 को प्राप्त हुआ था।

New Delhi, the 25th September, 1985

S.O. 4735.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Punjab National Bank and their workmen which was received by the Central Government on the 9th September, 1985.

BEFORE SHRI I.P. VASISTH, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
CHANDIGARH.

Case No. I.D. 47/84

#### PARTIES:

Employers in relation to the management of Punjab National Bank, Chandigarh.

AND

Their Workman: Ragubir Singh

#### APPEARANCES:

For the Employers:—Sh. V.C. Jaitely

For the Workman: Sh. C.L. Bhardwaj

ACTIVITY: Banking

STATE: Haryana

#### AWARD

Dated the 26th of August, 1985

The Central Government Ministry of Labour in exercise of the powers conferred on them under Section 10 (1) (d) of the Industrial Disputes Act 1947, as per their Order No. L-12012/125/80-D.II(A) dated 7 November, 1981 referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication.



“Whether the action of the management of Punjab National Bank in relation to its Pay Office at Baroda (Haryana) in denying the payment of 1/3 of scale wages to Sh. Raghbir Singh, Sweeper is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled and from which date?”

2. Brief facts of the case according to the petitioner, are that he was appointed as a part-time sweeper by the Respd. Bank at their Baroda Pay Office (branch) in District Sonpet w.e.f. 31-12-74 @ Rs. 15/- per month, raised to Rs. 20/- per month w.e.f. 1-2-1979. It was complained that he was not allowed any other benefits admissible under modified Bank Award and Settlements to permanent part time employees even though he had to work on an average of more than 2 hours per day. Elaborating the nature of his job, the petitioner pleaded that he was required to sweep, clean and wash the office premises as detailed below:—

- (a) One Strong Room of 17'x14' size.
- (b) Banking Hall of 28'x30' size.
- (c) Veranda of 9'x30' size.
- (d) All tables, chairs, counter and bench meant for the customers.
- (e) Cleaning and washing Latrine on 3rd floor.
- (f) Occasional washing of the Manager's residence.
- (g) To bring water for the staff and customers from a well situated 200 metres away from the office premises.
- (h) To call customers from their residence, the Lumberdar of the area and other clients of the Bank as per directions of the Branch Manager.

3. From the petitioner's point of view he was entitled to one third scale wages along with all the fringe benefits payable to a member of the Subordinate Staff in the terms of Bipartite Settlements. Therefore, he raised a demand through his Union, for the appropriate relief but the Management was found unresponsive despite the intervention of the ALC (C) at the Conciliation stage and hence the Reference.

4. Resisting the proceedings, the Management pleaded that the reference has since become infructuous because the petitioner has resigned his job on 4-2-1983 and was thus no longer in their service. On merits they vehemently denied having assigned him any such duty which could require more than 6 hours' weekly input. To be precise they averred that he was appointed as a part-time sweeper on a fixed salary of Rs. 15/- per month and had only one Banking Hall measuring 28'x30' besides a 9'x30' Veranda running along the frontage of the Hall for daily cleaning and sweeping of course, once in a blue moon he also cleaned the Strong Room but otherwise he was never required to do any other work. So much so that they had another part-time employee for fetching water for the consumption of the staff and the customers. It was further pleaded that in terms of the 3rd Bipartite Settlement the petitioner's wages were raised from time to time and that at the time of his disengagement he was being paid @ 60/- per month.

5. In view of the comprehensive nature of the terms of reference the parties were straight away called upon to adduce evidence in support of their respective versions under the directions of my learned predecessor. Thus they adduced Verbal as well as documentary evidence which I have carefully perused and heard them at length.

6. In so far as the Management's preliminary objection against the maintainability of the Reference is concerned I find it completely devoid of force despite the common proposition that the petitioner had resigned his job on 4-2-83. The pertinent point is that at the time of Reference he was very much in their service, and otherwise also the definition of a "Workman" as laid-down in section 2 (s) of the I.D. Act is comprehensive enough to include even a discharged employee. Of course there seems to be dispute between the parties on the point of voluntary nature of that resignation but, for the obvious reason I would like to leave it alone lest it should be taken as an expression of mind on a con-

troversy which might be a subject matter of an independent Reference.

7. Be that as it may, in the totality of the circumstances I do not feel inclined to sustain the petitioner's cause. On his behalf it was vehemently argued that he had a long list of daily assignments and chores to keep him busy for any time between one to two hours. It was argued that besides cleaning the Banking Hall, Veranda and Strong Room the Petitioner was also obliged to bring water from a distant well; clean and wash the Latrine on the 3rd floor; become the public street in front of the Bank premises and dust the furniture used by the Staff and customers of the bank. Moreover quite often he was also made to wash the Branch Manager's residence situated on the 1st floor and be present at his back and call to fetch the customers, from their houses. Lest but not least the Petitioner highlighted the inspection report of the ALC (C) staff to show that he was putting in about 1-1/4 hours daily work in cleaning the Bank premises and the adjoining public street.

8. I am afraid, in his anxiety to press his point the learned Rep. for the petitioner adopted a lopsided and myopic approach in overlooking certain salient feature of the case. The first and foremost point is that the petitioner was never employed on the regular staff of the Bank. There was no explicit or implicit agreement fixing the duration of his duty; rather he was engaged on purely part time basis for a particular assignment at a fixed salary which kept on increasing at different stages by mutual adjustment. In a manner of speaking he was given an assignment which could be attended any time at his leisure in the early morning before the start-of-the business hours. From his own sworn statement recorded by my learned predecessor it is abundantly clear that the Bank premises used to be opened by one Om Parkash. Peon. Petitioner would have us believe that Om Parkash used to open the Bank at 9-00 A.M. but Om Parkash in his affidavit and cross-examination as MW1. clarified that he used to open the Bank premises at 9-30 A.M.; exposing thereby that the petitioner had no occasion to be on the job before 9-30 A.M. The petitioner's own witnesses Kailash Chand Gupta WW2 and Ram Kumar Gupta, WW3 admitted that the office timings of the Bank used to be observed from 10.00 A.M. onwards. It means that the entire cleaning process must have been completed by the petitioner during intervening 30 minutes i.e. between 9.30 A.M. to 10-00 A.M.

9. It hardly requires any emphasis that there is nothing on record to fault the testimony of Om Parkash which rather finds an echo of credibility in the admission of petitioner's own witness Kailash Chand Gupta WW2 that he (Om Parkash) used to open the Bank at any time between 9-00 to 9-30 A.M. In his affidavit the Petitioner had averred that he used to report at the Bank early in the morning at 9-00 A.M. because he used to hold the keys and open the bank himself. But surely enough he could not stick to such a made up version and that was how that, melting on the acid test of cross-examination, he affirmed the earlier proposition of Om Parkash opening the Bank. Similarly Kailash Chand also came out a cropper in his cross-examination when he tried to confuse the whole issue by saying that the petitioner used to do his job from 10.00 A.M. to 10.15 A.M. i.e. in only 15 minutes every day.

10. The petitioner's next witness Ram Kumar Gupta WW3 failed no better by claiming that it was a part of his duty to report at the Bank premises at 9-00 A.M. to open and clean it; that he was also required to take out the books, dust them off and then restore them to their proper place but he had nothing to do with the dusting of the furniture even though he was posted there as a peon. He came out with yet another interesting detail in the sense that the Bank had only the ground floor with it; meaning thereby that the petitioner's story of cleaning the latrine situated on the 3rd floor was a fake one.

11. On the other hand consistency of the Management's witnesses i.e. the concerned Assistant Officer Incharge A. K. Aggarwal M.W. 1, Peon Om Parkash M.W. 2 and cashier N.K. Sharma. M.W. 3 could not be shaken despite grilling cross-examination. They categorically deposed that Smt. Bhateri Devi used to fetch water for the bank and was being paid separately on vouchers; to put it in other words, the petitioner had no function to bring water for his

Employer. Similarly they also deposed that normally the Bank used to be opened at 9-30 a.m. and the entire cleaning process used to be completed by 10.00 a.m. i.e. by the time of the start of the business hours.

12. The petitioner's contention that none could possibly broom and clean the Bank premises with a covered area of little over 1100 sq feet, in only half an hour is not tenable because it depends from person to person as to what particular time is consumed by him in doing such job. A conscientious worker would like to utilize his time in doing the job expeditiously whereas a lazy or slow worker could prolong it to suit his own convenience. And otherwise also the argument built around the total covered area under the Bank is misconceived because it is aimed at getting the benefit of the memorandum of settlement Ex. W5 dated 7-5-84 which itself came into force w.e.f. 1-1-84 i.e. after the petitioner's disengagement on 4-2-83 in pursuance to his resignation.

13. As regard the inspection note of an official of the ALC (C); suffice to say that it never formed a part of evidence before this Tribunal. He was not even offered for the purpose of cross-examination, though at its best his report to the ALC (C) itself was nothing more than a mere opinion and that too with no credentials of an Expert.

14. Hence for the reasons recorded above I find no impropriety in the action of the management in denying the payment of 1/3rd of scale wages to the petitioner Raghubir Singh and, as such, return my Award in their favour.

Chandigarh.

I.P. VASISHTH, Presiding Officer

[No. L-12012/125/80-D, II(A)/D, IV (A)]

का. आ. 4736 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. कानपुर के प्रबंध-तंत्र में सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निहित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 9 सितम्बर 1985 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 4736.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Hindustan Commercial Bank Limited, Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 9th September, 1985.

BEFORE SHRI R. B. SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL  
KANPUR.

Industrial Dispute 230/1983.

Reference No. L-12012/2/83-D-IV(A), Dated 1st Sept. 83  
In the matter of dispute between

Shri P. N. Tripathi, C/o The General Secretary, Hindustan Commercial Bank Limited, 8/75 Arya Nagar, Kanpur.

AND

The General Manager, Hindustan Commercial Bank Limited, Head Office, Birhana Road, Kanpur.

APPEARANCES :

Shri J. C. Dhawan representative—for the workman,  
8/75 Arya Nagar, Kanpur.

Shri B. C. Agrawal representative—for the management.

## AWARD

1. The Central Government, Ministry of Labour, vide its notification No. L-12012/2/83-D-IV(A), dated 1st September, 1983, has referred the following dispute for adjudication;

Whether the action of the management of Hindustan Commercial Bank Limited, Kanpur, in relation to their Barabanki Branch in denying promotion to Shri P. N. Tripathi, Peon cum Waterman with effect from 30-9-76 is justified? If not, to what relief is the workman concerned entitled?

2. It is common ground that the workman Shri P. N. Tripathi is cashier from 2-8-80. The workman Shri Tripathi was initially appointed on 17-6-72 as peon cum water man at Kanpur main branch. At the time of appointment he was High School passed and that he had not conceded his educational qualification, from the management bank. The promotions of the award staff in the cadre of cashier/Godown Keeper considered on the basis of seniority and the required educational qualification for such promotion is matriculation and in view of the bank's circular no. 390 of 31st March, 81 which is annexure A of the claim statement. The seniority is reckoned from the date of the appointment. That the management bank superseded to the workman Shri Tripathi and promoted several juniors in violation of provision of their own circular. For example Shri A. K. Tikka was appointed as peon cum water man from 1-8-72 who was promoted as clerk cum godown keeper from 30-9-76 Shri D. C. Mishra was appointed as water cum peon from September, 72 and was promoted as cashier cum godown keeper on 12-2-77 and Shri R. S. Dubey junior to workman Shri Tripathi was promoted by the management bank on 14-4-78. That despite repeated requests the management did not rectified the defect hence it is prayed that the seniority of the workman Shri P. N. Tripathi be made effective from 30-9-76 in supersession to the seniority given on 2-8-80 and the workman be recompensated from the loss for not giving him seniority at the proper time.

3. The management in its written statement has averred that prior to year 1976 there was no rule for promotion of sub staff and for the first time circular no. 91 of 15-9-76 provided the recruitment migration and promotion and it was also stipulated that promotion of the sub staff cadre will be restricted to the cadre of cashier cum godown keeper and for the promotion of that post the sub staff should have been passed matriculation examination or atleast have put in 4 years service before applying for promotion to the cadre of cashier cum godown keeper. That during the period some promotion were made in the year 1976 and the principal of seniority was not taken into account, but those who were willing to be considered were required to specifically apply for promotion after having passed the matriculation examination and on completion of atleast 4 years services in the sub-ordinate cadre, were only considered. That as per circular dated 15-9-76 it was provided that a register would be maintained for recording the request of the employees for migration/promotion and they would be considered strictly on the basis of the date of receipt of such requests. That the applicants were considered with the vacancies raised. The applicant Shri Tripathi applied later to Shri K. K. Tikka D. C. Mishra and Shri R. S. Dubey, and on that account the request of the applicant was considered after them. Thus the action of the management in not promoting the workman prior to 2-8-80 is justified and proper.

4. The management has filed circular no. 91 dated 15th September 76, wherein in para 5 of the said circular under the head of promotion from sub staff cadre to the cadre of cashier cum godown keeper it laid down that a member of sub staff should have passed matriculation examination and have put in at least four years service from the date of appointment on probation before applying for promotion to the cadre of cashier cum godown keeper. In note to this para, para a further lays down that a register will be maintained for recording the request of the employee for migration/promotion and they would be considered strictly on the basis of date of receipt of such requests and not more than 10 per cent of the vacancies in the category of clerk cum

godown keepers would be filled up by migration/promotion in a calendar year from sub staff.

5. In support of its contention the bank management examined Shri Umesh Saxena, Manager Personnel of Hindustan Commercial Bank Limited who filed his affidavit testifying that Shri K. K. Tikka, D. C. Mishra and Shri R. S. Dubey all had applied for promotion earlier than the workman, admitting that his date of appointment was a few months earlier to them. In cross examination the management witness has admitted that prior to 1976 promotion of sub staff persons was made on the basis of education i.e. High School Passed. According to him the representation of the workman for promotion was received in the management bank on 17-10-78 and all representative regarding the promotion of sub staff were entered in the promotion register and the vacancies were checked by Shri H. L. Jethali. In the end he stated that the promotion of workman was not considered earlier to Shri K. K. Tikka because his promotion application was not received till then and that the circular annexure 1 was on the basis of settlement of the Major Union.

6. The workman Shri P. N. Tripathi appeared in the witness box having set out his case in the affidavit filed by him. The workman has filed enclosure 1 whereby he requested to the Chairman Cum Managing Director of the management bank for promotion. He made subsequent application on 24-3-73 and on 8-9-76 for promotion on which he was intimated per annexure five that with reference to your representative we have been advised by Head Office that none of your representative is on your head office record except your representative dated 8th September, 76, which will be considered at the appropriate time. On oral representation to his application dated 17th June 72, the local branch manager was informed that the workman was not eligible for promotion to non sub cadre as he has not put in five years service according to bank's policy before July 76 and having put in 4 years service according to the procedure effective from 1st July 76. He was further informed that he could not be considered in preference to Shri Dinesh Chandra Sharma and Shri K. K. Tikka who had to be considered for promotion after they had put in three years service in the subordinate cadre in view of separate understanding in the matter. From this letter it appears that prior to 1st July 76 the promotion policy was different than one prevailing thereafter.

7. The management witness Shri Umesh Saxena along with his affidavit has filed circular no. 91 dt. 15th September 76 whereby, promotion could be possible after putting at least four years service in the sub-ordinate cadre. If this was so what was separate understanding with Shri K. K. Tikka and Shri D. C. Sharma. It is common ground that Shri P. N. Tripathi was senior most in the permanent appointment in sub staff cadre having date of appointment 17-6-72 and Mr. K. K. Tikka, R. S. Dubey and others all get appointment permanently later to Shri P. N. Tripathi. Thus four years service would be completed in the year 1976. Shri K. K. Tikka D. C. Mishra and R. S. Dubey were given promotion to the post of cashier cum godown keepers on 3-9-76, 11-2-77 and 14-4-78 respectively after completion of four years service. On this basis the workman also should have been given promotion in 76 but he was promoted to cashier cum godown keeper on 2-8-80.

8. No doubt workman Shri P. N. Tripathi started making representative for promotion as cashier cum godown keeper in leave vacancy since 73 on which he was intimated on 29th May, 75 that he could be considered for migration from one cadre to other only if he has put in five years service in the bank. The letter is enclosure 8 filed by the management.

9. As mentioned in circular no. 91 dated 15th September, 76 and according to it an employee who is making an application for migration for which a register will be maintained and promotion was to be considered strictly on the basis of receipt of such request. The management has admitted enclosure 5 filed along with affidavit of the workman that Head Office had not received any representation for promotion earlier except the representation dated 8th September, 76 and which will be considered at appropriate time. This means that the head office took note of the representation

made by the workman on 8th September, 76 for his promotion to cashier cum godown cadre and at that time the workman had completed four years service in that cadre as required according to the rules enforced at the relevant time. If his representation dated 8-9-76 was there with the management and he was senior to Shri K. K. Tikka the workman should have been given the permanent appointment on 20-9-76 first and not Shri K. K. Tikka. On the representation made by the workman against the promotion being given to Shri K. K. Tikka, D. C. Sharma and R. S. Dubey in cashier cum godown keeper cadre and ignoring his claim, the management replied per letter dated 28th January, 78 No policy prior to 1st July 76 has been lifted yet. The management informed the workman that the workman was eligible for promotion after having put in 5 years service in sub cadre before 1st July 76 and having put in 4 years service according to the procedure effective from 1st July 76. The management has however, informed that your case can not therefore be considered in preference to Shri Dinesh Chandra Sharma and Shri K. K. Tikka who had to be considered for promotion if they had put in 3 years service in subordinate cadre in view of separate understanding in the matter. In the absence of clear statement as to what was separate understanding regarding to the promotion of others was mala fide and ignoring the claim of senior workman Shri P. N. Tripathi. The workman such as to be whittled down on the ground of mala fide. The management having received representation of the workman on 8th September 76 after having put in four years service of the workman in view of circular no. 91 of 15th September, 76, the workman was entitled to be considered first or atleast with Shri K. K. Tikka and should have been given promotion first on 30-9-76 and not to Shri K. K. Tikka.

10. Under these circumstances and for the reasons discussed above believing the workman I hold that the action of the management of Hindustan Commercial Bank Limited Kanpur in relation to its Barabanki Branch, in denying promotion to Shri P. N. Tripathi workman is not justified and the result is that the workman will be deemed to have been promoted to the post of Cashier cum Godown Keeper w.e.f. 30-9-76 (30th September, 76) and further the workman will be entitled to recover the difference of wages that he would have earned and which he actually received from the management bank.

11. Under the circumstances of the case the workman is held entitled to get Rs. 200 as cost from the management.

12. I, therefore, give my award accordingly.

13. Let six copies of this award be sent to the Central Government, Ministry of Labour, for publication.

Dated : 2-9-75.

R. B. SRIVASTAVA, Presiding Officer  
[No. L-12012/2/83-D. IV(A)]

का.आ. 4737:---औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, न्यू इन्डिया एश्योरेंस कं. लि. कानपुर के प्रबंधन से सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, नई दिल्ली के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 12 सितम्बर 1985 को प्राप्त हुआ था ।

S.O. 4737.—In pursuance of section 18 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Central Government Industrial Tribunal, New Delhi, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the New India Assurance Co. Ltd., Kanpur and their workmen, which was received by the Central Government on the 12th September, 1985.

BEFORE SHRI O. P. SINGLA, PRESIDING OFFICER,  
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL,  
NEW DELHI

I. D. No. 29/85

In the matter of dispute between :

Shri O. P. Pal represented by  
Organising Secretary, General Insurance Employees  
Association,  
Northern Zone, 44/10, Regal Building,  
Connaught Circus,  
New Delhi-110001.

Versus

The Regional Manager,  
New India Assurance Co. Ltd.,  
15/60, Civil Lines, Kanpur (U.P.).

APPEARANCE :

Shri Amrik Singh Legal Adviser for Management  
None for the workman.

AWARD

Central Government, Ministry of Labour vide Order No. L-17012/57/84-D. IV(A) dated 9th July, 1985 made reference of the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the management of New India Assurance Co. Ltd. is justified in engaging Shri O.P. Pal at their Mathura & Agra Branches from March 1977 on daily wages for performing the duties of sub-staff and denying his regular scale of pay and permanent absorption ? If not, to what relief the workman is entitled ?"

2. Notices were issued to the parties and Mr. N.P. Upadhyay, Organising Secretary of the General Insurance Employees Association, New Delhi appeared for the workman and the case was adjourned on 1-8-85 for claim statement to be filed today. But none appeared for the workman today and Mr. Amrik Singh filed photo copy of a letter received from the workman in the following terms :

"BEFORE THE CONCILIATION OFFICER (CENTRAL)  
KASTURBA GANDHI MARG, NEW DELHI  
In the matter of an Industrial Dispute :

BETWEEN

THE MANAGEMENT OF THE NEW INDIA  
ASSURANCE CO. LTD. GREEN HOUSE,  
15/60, CIVIL LINES, KANPUR

AND

THEIR WORKMAN AS REPRESENTED BY GENERAL  
INSURANCE EMPLOYEES' ASSOCIATION,  
NORTHERN ZONE, 44/10, REGAL BUILDING,  
CONNAUGHT CIRCUS, NEW DELHI-110001.

CLAIM IN REGARD TO REGULARISATION OF  
SERVICES OF MR. OM PARKASH PAL

It is submitted that in the dispute as referred herein above the management is going to give appointment to the prayee and an agreement to this effect is made between Mr. O. P. Pal and the Management of New India Assurance Co. Ltd. So, it is requested to please subsidy this case.

The workman is desirous to withdraw the case, which please grant."

3. It appears that the Union is no longer interested in proceeding with the case of the workman before this Tribunal and, therefore, a 'No Dispute' award is made.

Further it is ordered that the requisite number of copies of this Award may be forwarded to the Central Government for necessary action at their end.

O.P. SINGLA, Presiding Officer  
3rd September, 1985.

[No. L-17012(57)/84-D. V(A)]  
K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 1985

आदेश

का. आ. 4738 :—कलकत्ता पत्तन न्यास के सम्बद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, जिनका प्रतिनिधित्व नेशनल यूनियन ऑफ वाटरफ्रंट वर्कर्स एण्ड कलकत्ता डाक वर्कर्स यूनियन करती है, एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है ;

और उक्त नियोजकों और उनके कर्मचारों ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 10 क की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थता के लिए निर्देशित करने का करार कर लिया है और उक्त माध्यस्थता करार की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजी गई है ।

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की उपधारा (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार उक्त माध्यस्थता करार को एतद्वारा प्रकाशित करती है ।

(करार)

(औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 क के अधीन)

पक्षकारों के नाम

नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री डी. पालित,  
श्रम सलाहकार और औद्योगिक संबद्ध अधिकारी, कलकत्ता पत्तन न्यास ।

कर्मचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : 1. श्री एम. दास गुप्ता,  
कार्यकारी अध्यक्ष,  
नेशनल यूनियन ऑफ वाटरफ्रंट वर्कर्स (इंटक)

2. श्री बी. प्रसाद,  
जनरल सेक्रेटरी,  
कलकत्ता डाक वर्कर्स यूनियन ।

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित औद्योगिक विवाद को श्री एच. जी. भावे, उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली 110001 के माध्यस्थता के लिए निर्देशित करने का करार किया गया है

(i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त  
विषय :—

(क) क्या स्टोर नियंत्रक के अधीन कोल हैण्डलिंग यूनिट में काम करने वाले और विभागीयकृत पोर्टरों का दावा कि उन्हें 1-8-78 में कोल बोट पर लस्कर के रूप में पदोन्नत करने के लिए विचार किया जाए, न्यायोचित है। जबकि तथ्य यह है कि जनरल स्टोर के पोर्टर ही ऐसी प्रोन्नति के पात्र हैं। यदि हां, तो इस प्रकार की प्रोन्नति के लिए कर्मकारों के इन दो ग्रुपों में क्या अनुपात होना चाहिए ?

(ख) क्या स्टोर नियंत्रक के अधीन कोल हैण्डलिंग यूनिट में संबंधित नम्बर टेकर्स का दावा कि उन्हें जनरल स्टोर में डिप्लोमरी मिरकार और डिस्पेंसर के पद पर पदोन्नत करने के लिए विचार किया जाए, न्यायोचित है जबकि तथ्य यह है कि इस प्रकार की प्रोन्नति के लिए जनरल स्टोर में कार्यरत नम्बर टेकर्स ही पात्र हैं। यदि हां, तो ऐसी प्रोन्नति के लिए कर्मकारों के इन दो ग्रुपों के बीच क्या अनुपात होना चाहिए ?

(ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अंतर्बलित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता भी सम्मिलित है।

1. कलकत्ता पत्तन न्यास, 15, स्ट्रण्ड रोड, कलकत्ता 700001 के नियोजक और उनके कर्मकार अर्थात् स्टोर नियंत्रक के अधीन कोल हैण्डलिंग यूनिट के पोर्टर्स और नम्बर टेकर्स जिनका प्रतिनिधित्व नेशनल यूनियन वाटरफ्रन्ट वर्कर्स (इन्टक), 15, कोल डाक रोड, कलकत्ता 700004 और कलकत्ता डाक वर्कर्स यूनियन, 27 बी, सर्कुलर गार्डन रोड रोड, कलकत्ता 700023 ने किया है।

(iii) विवाद में अन्तर्ग्रस्त कर्मकार का नाम और यदि कोई संघ प्रश्नगत कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करना हो, तो उसका नाम।

डी नेशनल यूनियन आफ वाटर फ्रन्ट वर्कर्स 15, कोल डाक रोड, कलकत्ता 700043 और कलकत्ता डाक वर्कर्स यूनियन 27 बी, सर्कुलर गार्डन रोड, कलकत्ता-700023

(iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या

लगभग 29000

(v) विवाद द्वारा प्रभावित या सम्भावित प्रभावित होने वाले कर्मकारों की प्राक्कनित संख्या

249

मध्यस्थ अपना पंचाट दो मास की कालावधि या इतने और समय के भीतर जो हमारे बीच पारस्परिक लिखित करार द्वारा बढ़ाया जाय, देगा। यदि पूर्व वर्णित कालावधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता, तो माध्यस्थम् के लिए निर्देश स्वतः रद्द हो जायगा और हम नए माध्यस्थम् के लिए बातचीत करने को स्वतंत्र होंगे।

पक्षकारों के हस्ताक्षर

ह./—

नियोजक का प्रतिनिधित्व करने वाले : (डी. पालित)  
श्रम सलाहकार और औद्योगिक संबद्ध अधिकारी,  
कलकत्ता पत्तन न्यास।

कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले

ह./—

(1) (एस. दास. गुप्ता)  
कार्यकारी अध्यक्ष, नेशनल यूनियन आफ वाटर फ्रन्ट वर्कर्स

(2) ह./—  
(बी. प्रसाद)  
जनरल सेक्रेटरी, कलकत्ता डाक वर्कर्स यूनियन

साक्षी

1. ह./—  
2. ह./—  
3. ह./—

मध्यस्थ की सहमति

मैं उपर्युक्त औद्योगिक विवाद, जो स्टोर नियंत्रक के अधीन कोल हैण्डलिंग यूनिट में कार्य कर रहे पोर्टरों और नम्बर टेकरों की पदोन्नति से संबंधित है, में औद्योगिक विवाद

अधिनियम, 1947 की धारा 10-क के अधीन मध्यस्थ के रूप में काम करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ।

ह./-

(एच. जी. भावे)

उप मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय)

नई दिल्ली और मध्यस्थ

[फाइल सं. एल-32013/1/85-डी. 4 (ए)]

के. जे. दैव प्रसाद, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 25th September, 1985

### ORDER

S.O. 4738.—WHEREAS an industrial dispute exists between the employers in relation to Calcutta Port Trust and their workmen represented by the National Union of Waterfront Workers and Calcutta Dock Workers' Union;

AND WHEREAS the said employers and their workmen have by written agreement under sub section (i) of section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) agreed to refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the Central Government a copy of the said arbitration agreement;

NOW THEREFORE in pursuance of sub-section (3) of section 10-A of the said Act, the Central Government hereby publishes the said agreement.

### AGREEMENT

(Under section 10-A of the Industrial disputes Act, 1947)

Name of the parties

Representing employer : Shri D. Palit,  
Labour Adviser & Industrial  
Relations Officer Calcutta  
Port Trust.

Representing workmen: (1) Shri S. Dasgupta,  
Working President  
National Union of  
Waterfront Workers  
(INTUC).  
(2) Shri B. Prasad,  
General Secretary,  
Calcutta Dock Workers  
Union.

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of Shri H.G. Bhawe, Deputy Chief Labour Commissioner (Central) Ministry of Labour, Government of India, Shram Shakti Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001.

(i) Specific matters in dispute

(a) Whether the claim of the Porters attached to Coal Handling Unit under the Controller of Stores and departmentalised with effect from 1-8-78, for being considered for promotion to posts of Lascar on the Coal Boats is justified, inspite of the fact that the Porters in General Stores are only eligible for such promotion. If so, what should be the ratio between these two groups of workmen for such promotion?

(b) Whether the claim of the Number Takers attached to Coal Handling Unit under the Controller of Stores for being considered for promotion to posts of Delivery Sircar and Despatcher in the General Stores is justified, inspite of the fact that the number Takers in the General Stores are only eligible for such promotion? If so, what should be the ratio between these two groups of workmen for such promotion?

(ii) Details of the parties to dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved :

The employer in relation to Calcutta Port Trust, 15, Strand Road, Calcutta 700 001 and their workmen, viz., Porters and Number Takers attached to Coal Handling Unit Under the Controller of Stores represented by National Union of Water-front Workers (INTUC), 15, Coal Dock Road, Calcutta 700 043 and Calcutta Dock Workers' Union, 27B, Circular Garden Reach Road, Calcutta 700 023.

(iii) Name of the workman in case he

The National Union of Waterfront Workers,

himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the workmen or workman in question :

15, Coal Dock Road, Calcutta 700043, and Calcutta Dock Workers' Union, 27B, Circular Garden Reach Road, Calcutta 700 023

Porters and Number Takers in the Coal handling unit under the Controller of Stores.

Sd/-

(H. G. BHAVE)

Deputy Chief Labour Commissioner (Central)  
New Delhi

&

Arbitrator

[F. No. L-32013/1/85-D.IV(A)]

K. J. DYVA PRASAD, Desk Officer

(iv) Total number of workmen employed in the undertaking affected

29000 approximately

(v) Estimated number of workmen affected or likely to be affected by the dispute :

249

The Arbitrator shall make his award within a period of two months or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case the award is not made within the period aforementioned, the reference to arbitration shall stand automatically cancelled and we shall be free to negotiate for fresh arbitration.

Signature of the parties

Representing employer Sd/-D. Palit  
Labour Adviser &  
Industrial Relations Officer  
Calcutta Port Trust.

Representing workmen (1) Sd/- S. Dasgupta  
Working President  
National Union of  
Waterfront Workers  
(2) Sd/-  
(B. Prosad)  
General Secretary  
Calcutta Dock Workers'  
Union

Witnesses ; 1. Sd/-  
2. Sd/-  
3. Sd/-

### CONSENT OF THE ARBITRATORS

I hereby give my consent to act as an Arbitrator under Section 10-A of the Industrial Disputes Act, 1947 in the industrial dispute over promotion of

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 18 मई, 1985

151/85-सीमा-शुल्क

का. आ. 4739.-केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खण्ड (ख) और (ग) द्वारा प्रवर्तित शक्तियों का प्रयोग करते हुए:-

- (1) सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर, जिलांग, की अधिकारिता के अन्तर्गत आने वाले स्थानों को, जो हमसे गलत सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हैं, भूटान से भूमि या अर्ध-देशीय जल मार्ग से आयातित या निर्यात किए जाने वाले माल को या ऐसे माल के किसी वर्ग की निकासी के लिए भूमि सीमा-शुल्क स्टेशन के रूप में नियत करनी है, और
- (2) उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट मार्गों को, जो उसके स्तम्भ 2 में प्रत्येक स्टेशन के सामने बजित हैं, ऐसे मार्गों के रूप में नियत करनी हैं केवल जिनसे होकर ही माल या माल का कोई वर्ग भूमि या अर्धदेशीय जल मार्ग द्वारा भूटान से या भूटान को लाया जा सकता है।

सारणी

क्रम सं.	भूमि सीमा-शुल्क स्टेशन	मार्ग
1	2	3
1.	उल्टापानी	बिष्णुपुरी से सरमंग (भूटान) को नहरवाली वन बोट कार्यालय होकर वन मार्ग।
2.	हर्तामर	मंथाईबारी से गैलेगफुंग (भूटान) को असम के कोकराझर जिले में रुर्णछाता और बक्सिरी होकर मोटर योग्य मार्ग।
3.	दांगंग	दांगंग से समदरूप-संकर (भूटान से) असम के कामरूप जिले में रांगिया-नमूलपुर मोटर योग्य मार्ग।

टी. एन. के. गोरी, अवर सचिव,

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 18 May, 1985

151/85—Customs

S.O. 4739.—In exercise of the powers conferred by clauses (b) and (c) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints—

- (i) the places under the jurisdiction of the Collector of Customs and Central Excise, Shillong, specified in column 2 of the Table appended hereto as Land Customs Stations for the clearance of goods imported or to be exported by land or inland water from or to Bhutan or any class of such goods; and
- (ii) the routes specified in column 3 of the said Table mentioned against each of the stations in column 2 thereof as the routes by which alone goods or any class of goods may pass by land or inland water from or to Bhutan.

Table

Sl. No.	Land Customs Station	Routes
1	2	3
1.	Ultapani	Forest Road from Bishmury to Sarbhang (Bhutan) via Naharali Forest Beat Office.
2.	ILATISAR	Motorable Road from Santhaibari to Gaylegphug (Bhutan) via Runikhata and Deosiri in the district of Kokrajhar of Assam.
3.	Darranga	Rangia—Tamulpur Motorable road from Darranga to Samdip—Jhankar (in Bhutan) in the district of Kamrup of Assam.

T.H.K. GHOURI, Under Secy.